This morning I came from New York. My flight No. was 106 fiom New York and via London it came to Bombay. *Afld* from Bombay I came to Delhi by flight No. 109. My luggage was booked from New York directly to Delhi and I arrived here at 3 in the morning. After my arrival here, my luggage consisting of two suit cases wa^ not located. On enquiry, they said that it will follow from Bombay. I waited fW another three flights which followed, till 6 A.M. It did not arrive.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R^MAKRISHNAN): You must thank God that you arrived safely.

SHRI MANUBHAI PATEL; All my clothes were in my suit case. I have come with unwashed clothes. I should not say it here, I know. This is the difficulty faced by lot of ordinary people also. Then they said : "You may lodge your complaints. I said: "I want my two suit cases. I do not want to make any complaint". They said: "We will inform Bombay". I then asked them: "Can't you telephone to Bombay? Have you not got some link with Bombay?" They replied: "We have booked a call to Bom-i> bay. We will receive their reply". After coming here at 10.30 or 11 A.M. I again telephoned to the Manager. His reply- was: "We have booked a call to Bombay to locate your luggage". I requested the Hon'ble Minister for Civil Aviation. He was kind enough to pass a message. But up-tin now there is no success.

I have to leave to day. I came this morning to attend Parliament session. ' I have to go back to my home town without my luggage. This is not only my personal experience. At the airport I saw—I counted them—more than 90 pieces of baggages. People were standing here and there. One lady had come from New York with two young kids. She was going to Patiala because her brother-in-law had expired. She had four pieces of 447 R. S.—9 luggage. She was yet to receive one out of them.

Is this the efficiency of Air India? We often speak about the efficiency Of Air India and the huge profits they have made las^ year and before that. But as far as the organisation aspect is concerned and as far as the management of international luggage is Concerned'. I think there is utter failure. Through you, I request the Government to kindiy look into this and see that the passengers are not harassed like this.

RESOLUTION FOR PROVIDING FREE AND COMPULSORY EDUCATION FOR ALL CHILDREN UNTIL THEY COMPLETE THE AGE OF EIGHTEEN YEARS

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): Let us now take Up Private Members' Resolutions. Shri Maurya.

SHRI BUDDHA PRIYA MAURYA (Andhra Pradesh); Sir, I beg to move the following Resolution:

"This House expresses its deep concern over the fact that even after thirty six years of Independence the number of illiterates is on the increase which is one of the major causes in weakening the fabric of national unity by en-. couraging flssiparous tendencies in the name of caste and religion; and therefore, enjoins upon the Government to take expeditious steps, by amending the Constitution, if necessary, for providing free and compulsory education for al children until they complete the age of eighteen years as an initial measure to combat iliteracy, poverty i the scourge of social evils and to strike at the root of various flssiparous tendencies in the country."

श्रीमन्, मुझ पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय सदन मेरे इस प्रस्ताव को सर्व-सम्मति से पारित करेगा । मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि माननीय संसद्

[श्री बुद्ध प्रिय मौर्य]

सदस्य दलों की राजनीति से ऊपर उठ कर खुले दिल और दिमाग से इस प्रस्ताव पर चलने वाली बहस में हिस्सा लेंगे । मैं इसी विश्वास के साथ अपने विचार सदन में रखने जा रहा हूं । भारत का अतीत दुनिया के बुद्धिजीवियों से छिपा नहीं है । भारत की पवित्र भूमि से वेदों के रूप में, ऋषियों की तपस्या के रूप में बुद्ध की अहिंसा, जन मुनि महावीर की मानवता के संदेश और करुणा की शिक्षा आदि तमाम संसार में फैलीं । एक समय था जब हमारी सभ्यता के चर्चे, हमारी शिक्षा और साधना के चर्चे पूरे संसार में हुआ करते थे । हमीं ने वेदों की वाणी के जरिये से पूरे संसार के मानवों को संदेश दिया कि...(**व्यवधान**) पूरे विश्व को, पूरे संसार को एक कुटुम्ब मानकर चलो । हमारे यहां माननीय मकवाणा जी बता रहे हैं, और मैंने भी देखा है सदन के बाहर भी कि यह सब इस बिल्डिंग पर लिखा है ।

मैं यह अभिमान तो नहीं करता कि भारत विद्वता में अद्वितीय रहा लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हम संसार के गुरु रहे हैं । हमीं ने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास की परम्परा संसार को दी । यदि इसी को मान लिया जाय तो पूरे संसार की आबादी की समस्या हल हो जाये । लेकिन दुर्भाग्य से वह भारतवर्ष जिसकी सभ्यता ने पूरे संसार को प्रभावित किया वही वर्ण व्यवस्था का शिकार हो गया । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अति शूद्र की परम्पराएं पड़ीं और चलीं । हो सकता है कि किसी समय वर्ण व्यवस्था की आवश्कता रही हो, मैं उस पर आज के दिन नहीं जाना चाहता लेकिन निश्चित रुप से जिस समय मनु की मनुस्मृति ने यह निश्चय कर दिया कि शूद्र और अति शूद्र को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, उसी समय से हमारा पतन प्रारम्भ होता है और हमारा पतन यहां तक पहुंचा कि हमने दासता का एक लम्बा सफर तय किया । मैं इतिहास का विद्वान नहीं रहा । लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि जितने लम्बे अर्से तक भारतवर्ष गुलाम रहा, शायद इतने लम्बे अर्से तक दुनिया का कोई मुल्क गुलाम नहीं रहा । मुट्ठी भर अंग्रेजों ने हमको गुलाम बना लिया था । लेकिन उस अंधेरे में प्रकाश की एक किरण आई । 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ में सैकेण्डरी एजूकेशन के बारे में सोचा गया । मैकाले हों या विलियम बेंटिन्क हों या इन्हीं से जोड़ दीजिए और दूसरे लोगों को, शायद इनको आवश्यकता थी कि भारत को लम्बे अर्से तक गुलाम रखने के लिए यहां पर एक ऐसी शिक्षा की प्रणाली चलायी जाये जिससे कि हमको शिक्षित सस्ते और अच्छे क्लर्क और सरकारी नौकर मिल सकें उसी परम्परा के अन्तर्गत 1835 से लेकर लगातार इस दिशा में हम चलते रहे । इस प्रणाली को इस वजह से मैं कह रहा हूं कि आज दुर्भाग्य से उसका बहुत कुछ अंश चल रहा है । राजा राम मोहन राय को इससे प्रेरणा मिली और इन्होंने इसको बढ़ावा देना शुरु किया । यह बहुत बड़ी बात है । मैं इसके इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं । वुडडिस्पैच के नाम से 1854 में बहुत लम्बे पैमाने पर शिक्षा का जाल इस देश में फैलाया था, लेकिन 1857 में सकेण्डरी एजुकेशन को एक आघात पहुंचा क्योंकि 1857 से युनिवर्सिटी की शिक्षा ने सैकेण्डरी एजुकेशन को केवल उसमें प्रवेश पाने का द्वार बनाया । उसका स्तर गिरा ।

इन्टर कमीशन 1882—इसी सिलसिले को एक कड़ी है । 1882 से 1902 तक

हायर सैकण्डरी एजुकेशन में काफी बढ़ोतरी हुई । सरकार ने जिम्मेदारी ली थी हायर सैकण्डरी एजुकेशन की, लेकिन धीरे-धीरे उसको वापिस ले लिया केवल प्राइमरी एजुकेशन की जिम्मेदारी अपने ऊपर रखी और इसको छोड़ दिया मदद देकर स्कूलों को चलाने वालों पर ।

श्रीमन्, आज जो मेरा प्रस्ताव है, उसकी प्रेरणा संविधान से मिली है । संविधान का रूप और कंस्टीट्यूएंट-असेम्बली के जरिए डाफ्ट कंस्टीट्यूशन बना उसमें यह जो शब्द आए थे, यह सर जान सार्जेंट—who was educational adviser to Gov ernment उस इनसान ने पहली बार भारत की भूमि के लिए यूनिवर्सल कम्पलसरी और फ्री एजुकेशन की बात कही थी । वहीं से प्रेरणा लेकर कि छह वर्ष से चौदह वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क अनिवार्य शिक्षा मिले, चाहे वह किसी भी धर्म और जाति के हों, अनिवार्य इसलिए कि गरीब का छह वर्ष से चौदह वर्ष तक का बालक-बालिका परिवार में कमाने वाला हो जाता है, इसलिए अनिवार्य इस वजह से रखा गया कि अगर कोई कमाई के लालच में बच्चे को न भेजें, तो उसको कानून की गिरफ्त में लिया जाए और सजा दी जाए और आज बहुत से मुल्कों में यह परम्परा है भी, और निशुल्क इसलिए क्योंकि भारत में बहुत से लोग वाल्क बहुत बड़ा बहुमत गरीब है या गरीबों की रेखा के नीचे है । इसलिए यह सिद्धान्त दिया गया ।

1948 में सैंट्रल एडवाइजरी बोर्ड को सिफारिशें यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, 1949, सैकेण्डरी एजुकेशन कमीशन, 1952, एजुकेशन कमीशन, 1966, यह तमाम इस आर्टिकल 45 की बैकग्राउंड में है ।

श्रीमन्, मैंने अभी निवेदन किया था कि देश के नेताओं ने संघर्ष करके जनता के आशीर्वाद और सहयोग से अंग्रेज को बाहर निकाल दिया देश आजाद हुआ। कंस्टीट्यूएंट असेंबली के जरिए संविधान बना। संविधान बनाने वाली एक कमेटी बनी, मसौदा बनाने वाली एक कमेटी बनी । यह समय की पुकार थी और कांग्रेस के नेताओं को दूरंदेशी थी उस वक्त कि उन्होंने इस देश के प्रति शोषित सर्वहारा समाज में जन्म लेने वाले परम पूज्य डा० बाबा साहब अम्बेडकर को मसौदा बनाने वाली कमेटी का अध्यक्ष बनाया और जिस समय ड्राफ्ट कंस्टीट्यूशन तैयार हुई, उस ड्राफ्ट कंस्टीट्यूशन में आर्टिकल 36 में यह व्यवस्था की गई थी । I am quoting from the draft Constitution, pages 14—36:

"Every citizen is entitled to free primary education and the State shall endeavour to provide, for a period of 10 yeara from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of 14 years."

श्रीमन्, इसमे कुछ कनफ्यूजन था । कंस्टीट्यूएंट असेम्बली की डिबेट चली । कंस्टीट्यूएंट असेम्बली की डिबेट मे इस कनफ्यूजन को भी परम पूज्य डा० बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ कर दिया । उन्होंने जवाब देते हुए कहा, मैं कोट कर रहा हूं, कांस्टीट्यूएंट असेम्बली डिबेट्स, वोल्यूम 12, पेज 540 :

"I am not prepared t_0 accept the amendment of my friend, Mr. Nazi-ruddin Ahmad. H_e seems to think that the objective of the rest of the clause in article 36 is restricted to free primary education. But that is not so. The clause, as it stands after the amendment, is that every

[Shri Buddha Priya Maurya]

child shall be kept in an educational institution under training until the child is of 14 years. If my hon. friend, Mr. Naziruddin Ahmad, had referred to aticle 18 which formed part of the Fundamental Sights, he would have noticed that provision is made in article 18 to forbid any child being employed below the age of 14 years. Obviously, if the child is not employed below the age of 14 years, the child must be kept occupied in some educational institution. That is the object of article 36 and that is why I say the word "primary" is quite inappropriate in that particular clause and I, therefore, oppose th$_e$ amendment."

And the words "Primary Education" were dropped.

श्रीमन्, संविधान के आर्टिकल 45 में यह व्यवस्था हो गयी । आर्टिकल 45 में कोट कर रहा हूं :

"The State shall endeavour to provide, within a period of 10 yearr from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of 14 years."

श्रीमन्, यह व्यवस्था है । इस व्यवस्था पर आगे कहने से पहले मैं आर्टिकल 24 को भी यहीं पर कोट कर देना चाहता हूं । 24 आर्टिकल कहता है ।

This article is under the Chapter on Fundamental Rights. It is not under the Directive Principles, as Article 45 is. It says;

"No child below the age of fourteen years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in an$_y$ other hazardous em ployment."

श्रीमन्, मुझे बहुत ही दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि संविधान 26 जनवरी 1949 को अधूरा और 26 जनवरी 1950 को पूरा लागू हो गया, लेकिन आज तक आर्टिकिल 45 को लागू नहीं किया गया । विधान-निर्माताओं ने इस को यहीं नहीं छोड़ दिया, सरकार की मर्जी पर नहीं छोड़ दिया था । मैं मानता हूं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को सरकार न माने तो अदालत के जरिए एनफो नहीं करवाया जा सकता जिस तरह फंडामेंटल राइट्स को कराया जा सकता है, लेकिन निश्चित रूप से प्रदेशों और केन्द्र की सरकारें, चाहे जितना उस से अलग हटने की कोशिश करें संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक दिशा देते हैं, जो भी सरकार होगी उस दिशा की तरफ चलेगी । 36 वर्ष आजादी आये हुए, अभी तक इस दिशा में कदम अधूरे ही नहीं बहुत अधूरे हैं । आज के दिन मैं ने इसी वजह से कहा कि दल से ऊपर उठ कर इस पर चर्चा हो । कोई भी दल और कोई भी दल का नेता आज भारतवर्ष में, वह चाहे जिस विचारधारा का हो यह नहीं कह सकते कि वह सत्ता में नहीं रहे । हम सभी किसी न किसी रूप में सत्ता में रहे । आज भी कई प्रदेशों में विरोधी दलों की सरकारें हैं और वे लोग जिन्होंने आज दल बनाये हैं वे भी किसी न किसी दिन और उन में से बहुत से तो 35 वर्ष और उन में से बहुत से 20 वर्ष और उन में से बहुत से 10 वर्ष और काफी लोग लम्बे समय तक मंत्री और मुख्य मंत्री और केन्द्र की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे । इस लिये आज कोई भी व्यक्ति विशेष जो इस देश में यह दावा करता है कि वह जन नेता है वह इस जम्मेदारी से अपने को अलग नहीं कर सकता । हम सब इस में शामिल हैं । हमारी उपलब्धियां हैं, मैं मानता हूं । उपलब्धियों के मामले में हम उन को

नजरअंदाज नहीं कर सकते, उपलब्धियां हैं शिक्षा के क्षेत्र में भी हैं और दूसरे क्षेत्र में भी हैं, लेकिन मैं इस बात पर चर्चा कर रहा हूं कि केवल शिक्षा के क्षेत्र में जहां अंग्रेज 27 यूनिवर्सिटियां छोड़ कर गये थे वहां आज 123 यूनिवर्सिटियां हैं, जहां मुश्किल से इस मुल्क में एक लाख प्राइमरी स्कूल हुआ करते थे आज 5 लाख प्राइमरी स्कूल हैं । मैं इस ओर नहीं जाना चाहता, उपलब्धियां हैं, निश्चयपूर्वक हैं और उन में सभी दलों का और नेताओं का और विशेष तौर से देश की जनता और सत्ताधारी दल का सहयोग है, हमारी उपलब्धियां हैं, सत्ताधारी दल की विशेष तौर से हैं, मैं मानता हूं, लेकिन मैं चर्चा कर रहा हूं आर्टिकिल 45 की । माना कि आर्टिकिल 45 डाइरेक्टिव प्रिंसिपुल्स में आता है लेकिन अभी मैंने जो आप के सामने आर्टिकिल 24 कोट किया, यह तो फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में है । इस का अर्थ मैं एक साधारण एडवोकेट के नाते, एक साधारण अध्यापक के नाते, एक साधारण संविधान का विद्यार्थी होने के नाते यही लगाता हूं कि सरकार ने जाने या अनजाने 14 वर्ष तक तमाम बालकों को जिन को शिक्षा अनिवार्य नहीं दी उन बालकों और बालिकाओं को नौकरी करने के लिये कमाई करने के लिये रोजी कमाने के लिये उकसाया, बढ़ावा दिया । यदि हम ने अनिवार्य शिक्षा को लागू कर दिया होता 1960 तक और इस देश के तमाम बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाती तो मेरा विश्वास है कि आज जो बच्चों को 14 वर्ष तक के बच्चों को खेत मजदूर के रूप में काम करना पड़ता है, छोटे छोटे होटलों और ढाबों में प्लेट साफ करने का काम करना पड़ता है छोटी-छोटी फैक्टरियों में और खतरनाक काम करने पड़ते हैं वे नहीं करने पड़ते और 14 वर्ष तक के बच्चों से कोई काम न ले इस की रोक करना इस के ऊपर पूरे तौर से हावी होना सरकार का कर्तव्य है । यह सरकार के अधिकार में है। सरकार का फर्ज हो जाता है । लेकिन सरकार अपने इस कर्तव्य का पालन करने में चाहे वह प्रदेश की सरकारें हों या केन्द्र की सरकार हो सफल नहीं हुई । उन्होंने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया । मैं, श्रीमन्, इस ओर भी आप का ध्यान ले जाना चाहता हूं . . . (**समय की घंटी**)

उपसभाध्यक्ष श्री आर० रामाकृष्णन: आप को आधा घंटा हो गया । आप 5, 10 मिनट और बोल लीजिए ।

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य : श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा हूं कि मेरा तोता टूट जाता है । मैं अपने आप कब रुक जाऊं ?

उपसभाध्यक्ष (श्री आर० रामाकृष्णन) 10, 15 मिनट और ले लीजिए ।

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य : मैं 4 बजे अपने आप रुक जाऊंगा ।

3 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): Now you collect your thoughts and speak at length.

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य : श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि देश में ही नहीं पूरे संसार में एक अजीब माहौल है आज के युग में । पूरे संसार में आज रक्षा पर 600 बिलियन डालर खर्च हो रहा है और शिक्षा पर उसका दसवां हिस्सा भी नहीं । पूरे देश के बजट के आंकड़े मैं कोट करना नहीं चाहता क्योंकि समय की

[श्री बुद्ध प्रिय मौर्य]

कमी है, समय मेरे खिलाफ बहुत तेजी से भाग रहा है । हमारे देश में भी मैं यह मानता हूं हमारे आस-पड़ोस में हिन्द महासागर में बहुत बड़े फौजी अड्डे बनाए जा रहे हैं । कभी-कभी फजाएं, कभी-कभी तर्जे अमल कुछ अजीब सा हो जाता है । कल तक भी जो हमारे शरीर के अंग थे उन पर भी भरोसा करना मुश्किल हो जाता है । मैं मानता हूं रक्षा को भुलाया नहीं जा सकता । लेकिन रक्षा को न भुलाएं रक्षा पर भारत सरकार 6633 करोड़ रुपया बजट रखे मेरे जैसे व्यक्ति को इस पर ऐतराज नहीं हो सकता क्योंकि हम पूंजीवादी व्यवस्था और सभ्य कहने वाले राष्ट्रों पर भरोसा नहीं कर सकते और हम अपनी रक्षा को किसी भी कीमत पर भुला नहीं सकते । मैं मानता हूं कि यह 6633 करोड़ का जो बजट रक्षा के लिए है उसे रखिए। लेकिन शिक्षा का बजट 340 करोड़ का है और वह भी पता नहीं पूरा इस्तेमाल होगा या नहीं, वह भी पता नहीं खर्च हो पाएगा या नहीं । शिक्षा को भुलाकर आप व्यक्तियों का निर्माण नहीं कर रहे हैं, आप बड़ी-बड़ी बिल्डिगें, 5 सितारा होटल, बड़ी-बड़ी-सड़कें, बड़े-बड़े कारखाने ही बना रहे हैं और जो समाज मानव समाज का निर्माण नहीं करता है, वह विनाश की ओर चलता है और अंत में लोप हो जाता है । शिक्षा के ऊपर मौलाना आजाद राष्ट्रीय नेता से शुरू करके हम स्टेट मिनिस्टर पर थम गए । मुझे अफसोस है कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण जिसका कम से कम कैबिनेट स्टेटस होना चाहिए, उसको गिराकर स्टेट मिनिस्टर कर दिया गया । यह हमारी रुचि है शिक्षा की ओर । मुझे यह विश्वास है कि सरकारी पक्ष जिसका मैं भी एक साधारण सदस्य हूं, जहां इस प्रस्ताव की जान को मानकर अपने बड़प्पन का सबूत देगा, वहां शिक्षा के मंत्री का ओहदा भी बढ़ा कर स्टेट मिनिस्टर से कैबिनेट मिनिस्टर का करायेगा ।

श्री लाडली मोहन निगम (मध्य प्रदेश) : कांवेन्ट स्कूलों की बात क्यों नहीं कहते हैं ?

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य : मेरे मित्र नाराज हो जाएंगे ...(**व्यवधान**)

श्रीमन्, शिक्षा से भुखमरी जुड़ी है, शिक्षा से बेकारी जुड़ी है, शिक्षा से ज़रायम जुड़े हैं, शिक्षा से विकास जुड़ा है, शिक्षा से परिवार नियोजन की व्यवस्था जुड़ी है, ये शिक्षा से तमाम जुड़ी हुई चीजें हैं । उसके रूपों में मैं बाद में आऊंगा ...

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): शिक्षा से राष्ट्रीयता जुड़ी ...(**व्यवधान**)

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य: उससे भुखमरी जुड़ी है। मैं निश्चित पूर्वक आभार मानता हूं अपने माननीय मंत्री श्री कल्पनाथ राय जी का जिन्होंने मेरी जानकारी में और जोड़ दिया है । मैं हृदय से उसका आभारी हूं । निश्चितपूर्वक राष्ट्रीयता शिक्षा से जुड़ी हुई है। लेकिन मेरा संशोधन इसमें यह है कि अशिक्षित राष्ट्रीयता में शिक्षित से पीछे नहीं रहता । मैं आपसे निवेदन करने जा रहा हूं भूखमरी के बारे में, गरीबी के बारे में । दुनिया में ऐसा कहा जाता है, यू०एन०ओ०, के आंकड़े यह कहते हैं कि दुनिया में 70 करोड़

इंसान गरीबी की रेखा के नीचे हैं। 70 करोड़ इंसान पूरी दुनिया में गरीबी की रेखा के नीचे हैं और इनमें से 35 करोड़ इंसान भारतवर्ष में गरीबी की रेखा के नीचे हैं । एक तरह से पूरी दुनियां की आधी गरीबी भारत ने अपने पेट में समेट ली। इस गरीबी को कैसे दूर किया जाए । इस देश के बालक और बालिकाओं को चाहे जिस धर्म, जाति और भाषा के हों उनको शिक्षित किया जाए ताकि वे चुनौती को स्वीकारें और आगे देश का निर्माण करें । भुखमरी की समस्या इससे जुड़ी हुई है ।

मैं बाद में लिटरेसी के आंकड़े दूंगा । मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या हम शिक्षा को बलाय-ताक रखकर या शिक्षा के साथ सौतेली मां का बर्ताव करके देश की भुखमरी की समस्या को दूर कर सकते हैं ? मुझे यहां के योजना बनाने वाले विशेषज्ञों की योग्यता पर शक होता है जिन्होंने शिक्षा को बहुत नीचे प्राइरीयोटी दी । एक तरह से बिल्कुल जमीन में लगा कर रख दी । मुझे उनकी दूरअंदाजी पर, मुझे उनकी योग्यता और क्षमता पर संदेह होता है । हम क्यों आ गये इस दुनिया में ? मैंने एक थोड़ा सा जिक्र किया था । फेमिली प्लानिंग भी इससे जुड़ी हुई है । परिवार नियोजन इससे जुड़ा हुआ है । क्या वजह है कि पढ़े-लिखे लोग इससे आगे नहीं आ रहे हैं । आज मेरे मित्र नहीं हैं, लेकिन मेरे मित्र जम्मू-कश्मीर के हैं, शहाबुद्दीन साहब यहां नहीं हैं मैं आज उनके लिये आंकड़े लाया था। खासकर मुसलमानों के लिये आंकड़े लाया था कि किस तरह से मुसलमान अपनी आबादी बढ़ाने के शोक में पीछे हटते जा रहे हैं । चार बीवियों का शोक बहुत पुराना हो गया । संविधान यह कहता है– यूनिफार्म सिविल लॉ । मैं इस पर बाद में आऊंगा । मैं आंकड़े देकर यह बताना चाहता हूं कि इस देश में किस तरह से इस्लाम के पाकीजा उसूलों से हट कर इस्लाम के बहुत से हामी, जिस इस्लाम ने मसावात का सबक दिया उसके बारे में आज आंकड़े देकर बताऊंगा कि किस तरह से जहां-जहां मुसलमान हैं वहां किस तरह से लिटरेसी का ग्राफ गिर रहा है । मैं इस पर चर्चा बाद में करूंगा । मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि परिवार नियोजन से भी यह जुड़ा हुआ है । यदि सन् 1960 में हमारे देश के नेताओं ने, हमारे देश के विधायकों ने, हमारे देश के माननीय सांसदों ने, हमारे देश के सरकारी कर्मचारियों ने, जनसाधारण ने, बुद्धिजीवियों ने श्रमजीवियों ने मिलकर इसको लागू कर दिया होता तो आज हम सन् 1983 में 14 वर्ष में 23 जोड़ दिया जाए 37 हो गया, तो 37 वर्ष तक के जितने भी नौजवान लड़के-लड़कियां हैं सब पढ़े-लिखे होते और निश्चियपूर्वक वे परिवार नियोजन का ध्यान रखते । अभी तो जो शादी की उम्र रखी है उस उम्र तक तो तीन बच्चे हमारे ब्रज में गरीब की बहू के चार बच्चे हो जाते हैं... (**व्यवधान**) । पांच भी हो जाते हैं । मैं शिक्षा को इन प्रश्नों से जोड़ रहा हूं । किस तरह से शिक्षा से भुखमरी को दूर किया जा सकता है, किस तरह से शिक्षा परिवार नियोजन की योजना सफल बना सकती है, ये सब प्रश्न इससे जुड़े हुए हैं । हमने योजनाएं बनाई, खेतों और कारखानों में उत्पादन बढ़ा, लेकिन खाने वालों की संख्या भी बढ़ती गई । इसीलिए मैंने कहा कि जिन लोगों ने योजनाएं बनाई उन विशेषज्ञों ने शिक्षा के ऊपर और क्यों नहीं दिया, यह हमारे लिए विचारणीय प्रश्न है । बगैर शिक्षा के परिवार नियोजन संभव

[श्री बुद्धि प्रिय मौर्य]

नहीं है और बगैर परिवार नियोजन के कोई योजना सफल नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति में हमारे देश से भुखमरी कैसे दूर हो? इन सब प्रश्नों को मैं शिक्षा के प्रश्न से जोड़ना चाहता हूं।

आज हमारे पूरे देश में जातीयता का बोलबाला है। मैंने कई बार कहा है—Caste system and Parliamentary democracy cannot go together. यदि हमें जनतन्त्र प्यारा है तो जातीयता की भावना को हमें जड़-मूल से समाप्त करना होगा। जनतंत्र और जातीयता साथ-साथ नहीं चल सकते हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि हमें जनतंत्र प्यारा नहीं है, जातीयता प्यारी है तो हमारे पूर्वज इसी तरह से गुलाम हो गये थे, काश, ऐसा बुरा दिन हमको देखने को न मिले, हमारी औलाद को फिर से गुलामी के दिन देखने को न मिलें। सही शिक्षा ही जातीयता की भावना को समाप्त कर सकती है। सही शिक्षा से जातीयता की समस्या को समूल नष्ट किया जा सकता है। हमारे देश में सही शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ। अगर हिन्दुस्तान में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हुआ होता तो जो आज कुछ फैक्ट्रियां शिक्षा के नाम से खुली हुई हैं, जहां पर कहीं तो मुल्ला पैदा होते हैं और कहीं पर पण्डे पैदा होते हैं और कहीं पर कुछ और पैदा होते हैं, वे पैदा न हुए होते। इन फैक्ट्रियों में इंसान बहुत कम पैदा होते हैं। कालेजों और स्कूलों ने इन फैक्ट्रियों का रूप ले लिया है। मेरा विश्वास है कि अगर हमने संविधान की इस भावना का आदर करके शिक्षा को लागू किया होता तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि इस देश का रूप ही कुछ और होता। जातीयता को रोकने में सही शिक्षा बहुत कारगर हो सकती है।

श्रीमन्, सिर्फ जातीयता की बात ही नहीं है, आज हमारे देश में चारों तरफ भ्रष्टाचार के बादल मंडरा रहे हैं। आज चारों तरफ भ्रष्टाचार का अंधकार देश को समेटे हुए है। भ्रष्टाचार का कलंक सिर्फ एक ही पार्टी की मौनोपाली नहीं है. यह सभी पार्टियों को घेरे हुए है। सही मायनों में भ्रष्टाचार पर सही शिक्षा के द्वारा ही काबू पाया जा सकता है क्योंकि भ्रष्टाचार करते समय अगर लेने या देने वाला पढ़ा-लिखा आदमी होगा तो वह सोचेगा कि कहीं पढ़ा-लिखा आदमी बड़े अफसर से शिकायत न कर दे। छोटा नेता भ्रष्टाचार करेगा तो उसको डर होगा कि कहीं बड़े नेता के पास शिकायत न हो जाय। इसलिए मैंने कहा कि भ्रष्टाचार के साथ भी शिक्षा का प्रश्न जुड़ा हुआ है। हमारे देश में क्राइम्स बढ़ते चले जा रहे हैं। इस देश में लगातार दहेज प्रथा को लेकर दुलहनें जलायी या जलती जा रही हैं। इस देश में लगातार कुरीतियां बढ़ती चली जा रही हैं। इनको काबू करने में शिक्षा बड़ी कारगर हो सकती है। कई बार ऐसे मौके आए हैं जब पढ़ी-लिखी लड़कियों ने दहेज की मांग करने पर शादी करने से इंकार कर दिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि शिक्षा कई रूपों में हमारे जीवन की समस्याओं से जुड़ी हुई है।

हमारे देश का हाल क्या है इसके मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। हमारी आजादी के बाद सन् 1951 में हमारी आबादी 36 करोड़ के आस-पास थी। आज हमारी आबादी 72 करोड़ की संख्या को छूने जा रही है। इससे आप

अन्दाजा लगाइये कि कितनी तेजी से हमारी आबादी में इन वर्षों में बढ़ोतरी हुई है । पिछले वर्ष में यह पापुलेशन ग्रोथ 1.9 फीसदी थी। पिछले साल में पापुलेशन ग्रोथ 1.9 फीसदी है (**व्यवधान**)... 2 प्रतिशत मानें, 2.1 प्रतिशत मान लीजिए, 2 प्रतिशत से ऊपर 2.5 प्रतिशत मान लीजिए । लेकिन मैं 2 प्रतिशत वाला नहीं, मैं तो जीरो ग्रोथ वाला हूं । जीरो ग्रोथ के लिये भी अनिवार्य हो जाता है कि हम इस दिशा में कदम मजबूती से उठायें। श्रीमन्, जिन आकड़ों के बारे में मैं निवेदन कर रहा था, उन आंकड़ों के बारे में मैं पहले शहरों के आंकड़े देना चाहता हूं । आकड़े तो बहुत हैं, पर थोड़े से ही दूंगा। जहां जहां शिक्षा है श्रीमन्, वैसे तो हमारे यहां देश के आधार पर आज लिट्रेसी 36.17 फीसदी है, 1971 में 29.45 फीसदी थी... (**व्यवधान**)...उपलब्धि तो मैं इसलिए मानता हूं कि बावजूद इसके कि आबादी बढ़ती जा रही है लेकिन तब भी लिट्रेसी बढ़ती जा रही है। अगर आबादी पर रोक लग जाये तो लिट्रेसी और भी ज्यादा बढ़ सकती है । श्रीमन्, लिट्रेसी में सबसे आगे केरल है । वहां पर लिट्रेसी 70.42थी अब वह 69.17 करीब-करीब 70 फीसदी है। यह दुर्भाग्य है कि औरतों में वहां भी लिट्रेसी का रेशियो मर्दों के मुकाबले में कम है । लेकिन देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान केरल का है।

श्री कल्पनाथ राय : लोवस्ट कौन है ?

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य : इस पर भी आ जाऊंगा श्रीमन् ।

चंडीगढ़, यह भी नम्बर दो पर आ जाता है, सैकण्ड डिवीजन में निकल जाता है। 71 में वहां लिट्रेसी 61.56 सैकड़ा था और 81 में 64.68 सैकड़ा हो गई है। श्रीमन्, दिल्ली...

डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला (महाराष्ट्र) : और बम्बई ?

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य : आपकी बम्बई के बगैर मैं कैसे चलूंगा ।

दिल्ली में 55.61 फीसदी थी श्रीमन्, 71 में, आज वह बढ़कर, लिट्रेसी, साक्षरता दिल्ली में 61.06 फीसदी हो गई। मिजोरम में 71 में लिट्रेसी 53.79 फीसदी थी और अब यह लिट्रेसी बढ़कर 59.50 हो गई है।

श्रीमन्, यह तो मैंने ऐसे प्रान्त लिये जहां पर आबादी कम है, शिक्षा ज्यादा है और इसका असर वहां पर आ रहा है। लेकिन श्रीमन्, जब मैं दूसरे प्रदेशों को लेता हूं तो उससे मेरे जैसा आदमी भयभीत हो जाता है। सिक्किम की मिसाल लाजवाब है। वह देश का अंग था अतीत में, देश का अंग है, बीच में छूट गया था। लेकिन सिक्कम में 71 में लिट्रेसी 17.74 फीसदी थी । श्रीमन्, मैं आज के इस शुभ अवसर पर सिक्किम से संबंधित सभी भाई और बहनों और साधनों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने लिट्रेसी का यह प्रतिशत 81 में बढ़ाकर, 17.74 से बढ़ाकर 33.83 कर लिया। लेकिन जहां तक जम्मू काश्मीर का सवाल है; वहीं रफ्तार बढ़ेगी जो पहले थी सो अब भी है । 1971 में जम्मू काश्मीर में साक्षरता 18.58 फीसदी थी अब वहां पर साक्षरता के आंकड़े ही नहीं

[श्री बुद्ध प्रिय मौर्य]

दिये गये हैं। लेकिन आंकड़ों को मैंने मालूम कर के देखा अपने ढंग से, आफिशियल फिगर्ज नहीं हैं, वहां पर साक्षरता 25 सैकड़ा से नीचे है। राजस्थान मे 1971 में 19 फीसदी थी आज 1981 में 24.05 फीसदी है। बिहार में 19.94 फीसदी थी और 1981 में 26 फीसदी है। उत्तर प्रदेश, वह भी इस मामले में बहुत पीछे है। 1971 में 21 फीसदी थी अब साक्षरता 27.38 फीसदी है। मध्य प्रदेश भी इसी के आसपास है। सन् 1971 में 22.14 फीसदी थी अब वहां पर साक्षरता 27.82 फीसदी है। श्रीमन्, यदि देश के ये हिन्दी भाषी क्षेत्र उसी तरह से तरक्की करते जिस तरह से केरल ने तरक्की की, चण्डीगढ़, दिल्ली और मिजोरम ने तरक्की की तो जो साक्षरता राष्ट्र के आधार पर 36 फीसदी है आसानी से 50 सैकड़ा पर आ सकती थी। लेकिन दुर्भाग्यवश हिन्दी भाषी क्षेत्रों में साक्षरता का ग्राफ उतनी तेजी से नहीं बढ़ा।

श्रीमन्, मैं अब शहरों के आकड़े लेकर के कुछ आपको कहने जा रहा हूं जिसमें कि मैंने शहाबुद्दीन साहब का जिक्र किया था। जहां तक हाइयेस्ट रिकार्ड का सवाल है अगर शहरों के आधार पर भी लिया जाए तो त्रिचुर जो केरल का एक अंग है वहां पर 81.09 फीसदी साक्षरता है। कोचीन केरल का एक शहर है वहां पर 78.45 फीसदी साक्षरता है। एलेप्पो, यह भी केरल का एक शहर है वहां पर 77.32 फीसदी साक्षरता है। तमिलनाडु भी इसका पड़ोसी होने के नाते या विकास और विद्या पर ज्यादा विश्वास करने के नाते तमिलनाडु भी काफी आगे है। तमिलनाडु का एक शहर है नागरकोयल, वहां पर साक्षरता, 75.71 फीसदी है और त्रिपुरा भी इसी तरह से आगे है। अगरतल्ला में साक्षरता 75.46 फीसदी है। यह तो है प्रोग्रेस की बात, उन्नति की बात, यह तो है तरक्की की बात लेकिन कुछ मित्र जो कभी-कभी साम्प्रदायिकता को राजनीति का हथियार बना कर के चलते हैं आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब मैंने आंकड़े देखे। सम्भल, उत्तर प्रदेश का शहर है। कितनी साक्षरता है? 24.84 फीसदी और बेचारी स्त्रियों में कुल 18 फीसदी। अमरोहा, उत्तर प्रदेश का ही शहर है यहां साक्षरता 27.75 फीसदी है और स्त्रियों में कुल 20 फीसदी साक्षरता है। रामपुर, यह भी उत्तर प्रदेश का एक शहर है, यहां नवाब साहब रहते थे अंग्रेजों के जमाने में वहां पर 33.24 फीसदी साक्षरता है। यह शहर कौन है? चाहे सम्भल हो, चाहे अमरोहा हो, चाहे रामपुर हो ये ऐसे शहर हैं जहां पर ज्यादा आबादी इस्लाम में यकीन करने वाले मुसलमान भाई बहुत ज्यादा अकसरियत में रहते हैं। जहां पर बहुमत में हैं, चाहे सम्भल हो, अमरोहा हो, रामपुर हो, यह जो 1981 का सेंसस है उसमें सबसे नीचे हैं, तमाम शहरों में सबसे नीचे हैं, इनसे और कोई नीचे नहीं है और यहां पर बहुमत, बहुत बड़ी अकसरियत मुसलमानों की रहती है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। जिस तरह से इस देश का कोई भी विशेष धर्म और जाति का व्यक्ति इस देश का अंग है उसी तरह से मुसलमान भी इस देश का अटूट अंग है। देश के बंटवारे पर भी उस समय पाकिस्तान मे, उस समय के बने हुये पाकिस्तान में गैर मुसलमानों के ऊपर कातिल की तलवार लटक रही थी और जब अंग्रेजों के इशारे पर जिन्ना साहब की जिद्द पर तथा

हमारी कमजोरी की वजह से बंटवारा हुआ तो ठीक उसी समय पर इस मुल्क के मुसलमानों के ऊपर भी कातिल की तलवार लटक रही थी। जो उतने खतरे को मोल लेकर, उतने खतरे का सामना करके इस देश में रुका, यकीनन वह देशभक्ती में किसी से कम नहीं, लेकिन दुर्भाग्य कि मुसलमान तालीम की तरफ कम झुके और उनके कुछ रहनुमा फिरकापरस्ती की तरफ ज्यादा जोर दे रहे हैं। आज यही वजह है कि आई० ए० एस० आई० एफ० एस० वगैरह में वे शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग वे शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग जिनके साथ कई जन्मों तक जानवरों से भी बुरा बर्ताव हुआ, सदियों तक हुआ, आज उनके लड़के जनरल में आते हैं, 22 शिड्यूल्ड कास्ट के लोग जनरल में आई०ए०एस० में आये तीन शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग जनरल में आये और मुसलमान की गिनती उस सिलेक्शन में कम हुई। क्या वजह है? इसकी वजह है कि मुसलमान तालीम की तरफ बहुत कम ध्यान दे रहे हैं और मौलवियों की तरफ बहुत ज्यादा। वह अपने तर्जेअमल में मौलवियों की तरफ ज्यादा ध्यान दें, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, पांचों वक्त की नमाज पढ़ें, मेरे जैसा इन्सान खुश होगा लेकिन जितना मजहब पर जोर है उतना तालीम पर भी जोर हो। लेकिन तालीम पर जोर नहीं हो रहा है। नारे लगा दिये जाते हैं तरह-तरह के, मैं इसमें सरकार की भी कमी मानता हूं। हो सकता है कि जहां पर मुसलमानों की बस्तियां हों वहां पर स्कूलों की तादाद उतनी न हो जितनी और एडवांस्ड कास्ट्स के लोगों के इलाकों में है। यह भी हो सकता है। लेकिन मैं यह निवेदन कर रहा था कि मुसलमान जो कल हिन्दुस्तान की उस मेन स्ट्रीम, धारा में आ गया है आज शिक्षा के अनादर के कारण वह उस मेन स्ट्रीम से हटता जा रहा है। इसके बारे में हमें बहुत सख्ती से, बहुत मजबूती से विचार-विमर्श करना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज आवश्यकता हो गयी है कि हम जीवन के हर क्षेत्र में इस बात को मजबूती से अपनायें। मुझे खुशी है कि सत्ताधारी दल ने और सत्ताधारी दल के प्रस्ताव के आधार पर भारत सरकार ने 20 नुक्ते के कार्यक्रम को अपनाया। मुझे खुशी है और उस 20 नुक्ते के कार्यक्रम में शिक्षा का ज्यादा से ज्यादा प्रसार और प्रचार हो इस मद पर जोर दिया गया है। मुझे इस बात से खुशी है कि देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 14 जनवरी, सन् 1982 को नये बीस सूत्री कार्यक्रम की आकाशवाणी से घोषणा करके उसमें विशेष स्थान उन्होंने आरम्भिक शिक्षा को दिया है। मैं उसी को कोट करने जा रहा हूं।

"We have still much to do to provide free and compulsory education to all children up to the age of 14. All of you know the situation in your own State. I should like to stress the importance of the education of girls. One more point. In my own State I find that text-books need revision, although some action has been taken. We must, all of us. try to avoid any type of parochial communalism, casteism of anything that can be divisive. They can create problems for sections of the population within the State or within its neighbouring State."

श्रीमन्, इस नये बीस नुक्ते के कार्यक्रम में भी शिक्षा के ऊपर काफी जोर दिया गया है। मुझे विश्वास है कि उसको कानून का जामा भी पहनाया जाएगा। कानून का जामा अगर पहना दिया जाए, तो उससे एक लाभ पहुंचेगा कि

[श्री बुद्ध प्रिय मौर्य]

अट्ठारह वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाना ही पड़ेगा।

उससे दूसरा लाभ यह पहुंचेगा कि जो बच्चे छोटी उम्र के हैं, उनको काम करने के लिए उनके परिवार के लोग या वे परिस्थितियों के दास होकर मजबूर नहीं होंगे। मैं आपसे एक और निवेदन इस संबंध में करना चाहता हूं और वह यह है कि मेरा विश्वास है कि माननीय संसद् सदस्य जब इसमें हिस्सा लेंगे, तो जरूर उस पर प्रकाश डालेंगे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज क्षेत्रीय भावनाएं, राष्ट्रीय भावनाओं से ऊपर बढ़ती चली जा रही हैं। आज क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दलों से उनकी गिरफ्त मजबूत होती चली जा रही है। आज भाषा को लेकर विरोध है। भाषा कभी भी विरोध का विषय नहीं होना चाहिए। भाषा के विषय में तो मेरीय ह मान्यता है कि जितनी आसानी से बालक और बालिकाएं अपनी मातृभाषा में शिक्षा को ग्रहण कर सकता है या कर सकती है उतना विदेशी भाषा, अंग्रेजी भाषा, फ्रेंच भाषा, रशियन भाषा, चाहे जैसी लचीची क्यों न हो, चाहे जितनी विकसित क्यों न हो, चाहे उत्तेजित और डाइनैमिक क्यों न हो, लेकिन बच्चे की बुद्धि का विकास जितना शक्ति के साथ, जितना क्षमता के साथ, जितना इरादे के साथ बच्चे की बुद्धि का विकास उसकी मातृ-भाषा में लालन-पालन करके, पठन-पाठन करके विकास किया जा सकता है, उतना विदेशी भाषा के आधार पर नहीं किया जा सकता है। मेरी यह प्रार्थना है कि इस देश में विदेशी भाषाओं को बढ़ावा मिले क्योंकि स्वयं गांधी जी ने यह कहा था कि मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा देश एक बंद कोठरी बन कर रह जाए, मैं चाहूंगा कि मेरे देश के मकान की खिड़कियां खुली रहें, ताकि सभ्य और प्रगतिशील राष्ट्रों की ताजा हवा भी यहां आए और हम उनके साथ मिल-जुल कर के चल सकें। मैं इस विचार का समर्थक हूं। मैं किसी भाषा का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मातृभाषा में जितना तेजी के साथ, जितनी मान्यता के साथ, जितनी मजबूती के साथ बच्चे की बुद्धि का विकास हो सकता है, उतना तमिल भाषा के मातृ-भाषा वाले बच्चे के दिमाग में हिन्दी से या अंग्रेजी से नहीं हो सकता। इसी तरह से मराठी और बंगला भाषा का है। इन तमाम भाषाओं में ऊंची से ऊंची शिक्षा बच्चे को मिल सके, इस तरह की व्यवस्था भी आज हमें करनी होगी।

मेरी यह मान्यता है कि जापान, जापान नहीं बनता अगर वहां की शिक्षा-दीक्षा जापानी भाषा में नहीं होती; मेरी मान्यता है कि जर्मनी, जर्मनी नहीं बनता, अगर वहां की शिक्षा दीक्षा जर्मन भाष में नहीं होती। मेरा यह विश्वास है कि रूस, रूस नहीं बनता, अगर रूस के बालक और बालिकाओं की रूसी भाषा में शिक्षा-दीक्षा नहीं होती। इसी तरह से भाषा में जब तक मातृभाषा में पठन-पाठन न हो, तब तक भारत विकसित नहीं हो सकता। उसके बच्चों की बुद्धि का विकास करके उसको आगे के दायरे में नहीं खड़ा किया जा सकता जब तक तक कि यहां के बच्चों की तालीम उनकी मातृभाषा के जरिए न हो। इसलिए जहां यह शिक्षा को प्रणाली अट्ठारह वर्ष के बालक और बालिकाओं को अनिवार्य हो, वहां यदि इसके लिए आवश्यकता पड़े, तो संविधान का भी संशोधन किया जाए।

मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि जहां यह व्यवस्था की जाए, वहां पर मैं यह भी आपसे प्रार्थना करूंगा कि संविधान में अगर आवश्यकता पड़े, तो संविधान में संशोधन कर दिया जाए क्योंकि डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्ज में केवल चौदह वर्ष के बालक और बालिकाओं की व्यवस्था रखी थी। चौदह वर्ष तक के बालक और बालिकाओं को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा मिले, यह हमारे नेताओं ने, पं० जवाहरलाल नेहरु ने, डा० बाबासाहब अम्बेदकर, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने यह उस वक्त सोचा था, यह मान्यता उस वक्त थी जब हम दुनिया में बहुत पीछे थे। आज दुनिया के उद्योग के विकास में हम दुनिया के दस अग्रिम राष्ट्रों में गिने जाते हैं। टैक्नीकल नो-हाऊ और परसोनेल का सवाल है, दुनिया के अग्रिम तीन मुल्कों में हमारी गिनती है।

उस समय निश्चयपूर्वक भारतवर्ष में यह चौदह वर्ष को बढ़ा करके अठारह वर्ष किया जाए—अठारह वर्ष की आयु के बच्चों को, बालक और बालिकाओं को अनिवार्य शिक्षा मिले, तो मेरा विश्वास है कि आज यहां के अति सर्वहारा समाज के लोगों को भी भीख की लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। मैं एक शोषित मां की कोख से जनमा हूं, मैं कभी फीस माफ कर नहीं पढ़ा, मैं कभी भीख मांग कर नहीं पढ़ा : मैंने मेहनत की, बी० एस-सी० की, एल० एल० बी० की, एल० एल० एम० किया, आज मैं जो हूं अपनी वजह से हूं, मेरी अपनी उपलब्धि है, यह मेरे अन्दर स्वाभिमान पैदा हुआ। मैं चाहता हूं कि इस देश के बालक-बालिकाओं को, चाहे वे जिस धर्म और जाति के हों उन को भीख न मांगनी पड़े, फीस न मांगनी पड़े, उनको अपने को अछूत मान कर वजीफा न मांगना पड़े, उनके अन्दर स्वाभिमान जागे, इस लिए 18 वर्ष के बालक-बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाय तो मेरा विश्वास है कि शोषित और सर्वहारा समाज के बच्चे फीस के या भीख के मोहताज नहीं रहेंगे।

श्रीमन्, आप ने मुझे बहुत समय दिया। उसके लिए मैं आपका आभार मानता हूं। माननीय सदस्य बहुत इच्छुक हैं बोलने के लिए, इसलिए मैं उनका और समय खराब नहीं करना चाहता। मैं आप के और माननीय सदस्यों के चरणों में नतमस्तक होते हुए एक ही प्रार्थना करता हूं कि इस भावना को स्वीकार करके आप इस प्रस्ताव को निर्विरोध पास करें। धन्यवाद।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (बिहार): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

"संकल्प की दसवीं पंक्ति के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

'और शिक्षा में एकरूपता लाने के लिए पब्लिक स्कूलों को समाप्त करने :'"

The questions were proposed

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN); Now the Resolution and the amendment are open lor discussion. Mr. Shiva Chandra Jha.

श्री शिवचन्द्र झा (बिहार) : उप-सभाध्यक्ष महोदय, बुद्धप्रिय मौर्य का जो यह प्रस्ताव है बहुत इनोकुअस है, जिसके सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। इतनी मेहनत करने की भी इनको जरूरत न होती, प्रस्ताव देखते ही हम सब कह देते हैं कि इस को मान लेना चाहिए, सदन में

[श्री शिव चन्द्र झा]

किसी को एतराज नहीं है, सरकार इसको मान ले, मैं इसका समर्थन करता हूं।

DR. MALCOLM S. ADISESHIAH (Nominated): Mr. Vice-Chairman, I heard in the English translation that Mr. Hukmdeo Narayan Yadav's amendment is that private schools are to be banned, whereas the official amendment of Mr .Hukmdeo Narayan Yadav circulated to us says "for closure of public schools to achieve uniformity in education." May I know from you which is correct?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): It is "public schools". That is the correct version.

श्री शिव चन्द्र झा : उप सभाध्यक्ष महोदय, इस में कोई विवाद नहीं है, इस प्रस्ताव को सरकार को मान लेना चाहिए। लेकिन मैं पूछता हूं कि क्या सरकार इस प्रस्ताव को मानेगी? नहीं मानेगी। क्योंकि अभी खुद प्रस्तावक महोदय ने बीस-सूत्री कार्यक्रम पढ़ कर सुनाया। प्रधान मंत्री जी क्या कहती हैं? प्रधान मंत्री कहती हैं 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एण्ड कम्पलसरी एजूकेशन। यह कहते हैं 18 साल तक के लिए, जो बीस-सूत्री कार्यक्रम के खिलाफ है, उस के अनुकूल नहीं है। बात खत्म हो जाती है, गिर जाती है, प्रधान मंत्री के प्रस्ताव के खिलाफ यह बात हो जाती है, कैसे सरकार मानेगी।

डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला : खिलाफ नहीं कह रहे हैं, एण्ड कर रहे हैं उसमें।

श्री शिव चन्द्र झा : बीस-सूत्री कार्यक्रम को संशोधित करिए इन के मुताबिक तब हो सकता है।

दूसरी बात, 18 साल तक के बच्चों को मुफ्त पढ़ाई देने के लिए कितना खर्चा होगा? क्या सरकार उसके लिए तैयार है? मैं यह नहीं कहता कि सरकार में क्षमता नहीं है। सरकार उसको मोबिलाइज नहीं कर सकती। क्या सरकार तैयार है उसको मोबिलाइज करने के लिए। ठीक ही बताया गया कि डिफेंस पर बड़ा खर्च हो रहा है, दूसरे महकमों पर बड़ा खर्च हो रहा है। क्या सरकार मोबिलाइज करने के लिए तैयार है। इसलिए बावजूद हम लोगों के समर्थन के यह सरकार हो खुद इस को मंजूर नहीं करेगी। यही दुख की बात हो जाती है।

प्रस्तावक महोदय ने और कई बातें रखीं। उन्होंने कहा कि शिक्षा मेरा कहना है कि शिक्षा ही बढ़ने से मसला हल नहीं हो जाता है?

उप सभाध्यक्ष महोदय, कल अपने भाषण में आपने एक बड़े पंडित का नाम लिया। आपने उसका स्मरण किया। मैंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया लेकिन आज अखबार में देखा वह बड़ा पंडित था रावण। आपने उसका स्मरण किया। रावण भी मामूली पंडित नहीं था। खुद मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने लक्ष्मण को कहा कि जाकर उसके चरणों में राजनीति सीखो लेकिन रावण ने क्या किया? वह बहुत शिक्षित था यह हम सब जानते हैं। बहुत शिक्षित होने से ही मसला हल नहीं होता। अब उन्होंने वैदिक काल की बात उठायी, महाभारत काल की। द्रोणाचार्य गुरू थे। सब को शिक्षा देते थे लेकिन अंगूठा ही काट लिया। इतना ही नहीं, उनकी आंखों के सामने द्रौपदी का चीर-हरण हो रहा था और वह टकुर टकुर देखते थे। आज भी वहां यह सब होता

है। इमरजेंसी में जनतंत्र का चीरहरण हो रहा था और सब शिक्षित लोग बाहर थे। बड़े-बड़े पंडित देखते थे जो कुछ हो रहा था और हम अशिक्षित लोग जेलों में बन्द थे। हम हजारों लाखों इंसान, अशिक्षित इंसान जेलों में थे और जब जनतंत्र का चीरहरण हो रहा था इमरजेंसी में तो पंडित लोग टुकुर टुकुर देख रहे थे। तो शिक्षा से ही काम नहीं चलता है। (व्यवधान) अब इस का मतलब आप कुछ लगावें या वह कुछ लगावें यह दूसरी बात है, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूं, मेरी बात सुनिये। हिटलर अशिक्षित नहीं थे। उसने शिक्षा पर ही किताब लिखी, लेकिन वह दुनिया को कहां ले गया इसको देखिये। इसको सब जानते है। मुसोलिनी अशिक्षित नहीं थे, लेकिन वह दुनिया को कहां ले गया यह हम सब जानते हैं। चर्चिल भी अशिक्षित नहीं था लेकिन भारत का दमन करने के लिये उसने क्या क्या किया वह हम सब जानते हैं। तो सवाल इतना नहीं है कि शिक्षा को बढ़ाने से ही हमारी पावर्टी या हमारे सोशल इविल्स खत्म हो जायेंगे। शिक्षा हो तो कैसी हो, उस का दृष्टिकोण क्या हो यह हमें सोचना चाहिए।

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य : सही शिक्षा का शब्द मैंने इस्तेमाल किया है।

श्री शिव चन्द्र झा : शिक्षा हो तो कैसी हो और जरूरत है कि हम उस दृष्टिकोण को साफ करें। प्रस्तावक महोदय की बात मैं कुछ समझा और कुछ नहीं समझा। उन्होंने बहुत कुछ मुसलमानों को कह दिया कि उनमें यह है वह है। लेकिन आप का दृष्टिकोण क्या है? गीता में लिखा हुआ है :—

"चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् गुण कर्म विभाजनः।"

चार वर्णों का बनाने वाला मैं हूं। है हिम्मत भगवान कृष्ण को ललकारने की कि उन्होंने गलत कहा था?

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य : हां, गलत कहा था।

श्री शिव चन्द्र झा : सवाल यह आ जाता है कि घर-घर में उनकी पूजा होती है। आप भी भगवान कृष्ण की पूजा करते होंगे। लेकिन गीता को लिखने का काम बाद में हुआ। भगवान कृष्ण के मुंह से यह कहलाया गया बहुत बाद में उस वक्त उस पंडित ने राजा के कहने से जिस को उस की जरूरत थी यह लिखा। इसमें शक नहीं कि गीता लिखने वाला स्किलफुल था। सारे भारतीय दर्शन को इस दर्शन की जरूरत थी। मुश्किल हो जाता है इरिकंसाइल को कंसाइल करना, लेकिन उसने कोशिश की है। है हिम्मत उसको कांट्रैडिक्ट करने की? हमारी बड़ी कोशिश होती है कि हमारे घर में सत्यनारायण की पूजा नहीं। मैं जब भी देहात जाता हूं तो अन्दर नहीं जाता। बाहर बैठा रहता हूं। या तो मैं प्रसाद के वक्त उसके पास पहुंच जाता हूं या प्रसाद मेरे पास पहुंच जाता है। तो सवाल यह है कि आपने एक सेक्टर पर तो हमला किया लेकिन दूसरे बड़े सेक्टर का दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है।

[उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश गोस्वामी) पीठासीन हुए।]

दृष्टिकोण आपका कैसे बदल जाएगा? वैज्ञानिक उसको बनाना पड़ेगा। वैज्ञानिक वह कैसे बनेगा? शुरू से सब बच्चे को स्कूल में वैज्ञानिक तरीके से पढ़ाया जाएगा कौन सी चीजें हम पढ़ायें जिनसे हमारे दृष्टिकोण की शुरूआत हो। जब आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश पढ़ायेंगे, एक क्रियेटर

[श्री शिव चन्द्र झा]

दूसरा पालक, तीसरा संहारक तो हो गया सारा काम चौपट। जब ऐजूकेशन और विकास की बात को हैमर नहीं किया जाएगा, इन पर जोर नहीं दिया जाएगा तो कैसे विकास होगा। यह भूमंडल, ब्रह्मांड कैसे बना, इसकी शुरूआत कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ। कहने का मतलब यह कि डार्विन, मर्क्स और आइंस्टाइन इन सबों के जो विचार है उनको देना होगा। गांधी के भी हैं; जवाहर के भी हैं, दूसरों के भी है लेकिन ये कुछ बुनियादी बातें है जिनको पढ़ाना बहुत जरूरी होता है ताकि दृष्टिकोण बदलें। आप भी जानते हैं कि बोलने के वक्त बहुत ही साइंटिफिक भाषण होते हैं, लेकिन मैं बिहार से आता हू, मुझे मालूम है कि 80 परसेंट हमारा काम वैदिक काल से चला आ रहा है। आप लड़ाई कीजिए, संघर्ष कीजिए, बगावत करके देखिए। हिन्दुस्तान में बगावत करने वाले, विचार रखने वाले भी हुए हैं। इन संतों के मुताल्लिक विचारक पहले भी हुए हैं, दार्शनिक भी हुए हैं जिन्होंने इन पर प्रहार किया है और आवाज उठाई है। क्या कहा कबीर ने :-

"पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहार घर को चाकी कोई न पूजे, बहि का आटा खाये।"

आज है कोई इन बातों को मानने वाला? उधर भी कबीर दास ने कहा है---

"कंकड़ पत्थर जोरि के, मसजिद लई बनाय तापर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाय?"

तो इन सिद्धान्तों को मानने वाले, समाज को अंधविश्वास से हटाने वाले दार्शनिक भी इस देश में पैदा हुए हैं।

उपाध्यक्ष जी, उन्होंने कुठाराघात किया और एक साइंटिफिक रेशनल अपना दृष्टिकोण रखने की कोशिश की जनता के सामने। सैकड़ों वर्षों पहले गुरु नानक देव थे जो एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने भी एक बड़ा आंदोलन चलाया अंध विश्वास के विरुद्ध उन्होंने भी कोशिश की लोगों के सामने सही दृष्टिकोण रखने की।

एक बार गुरु नानक दरिया में नहाने गए। वहां कुछ शास्त्री या पंडित लोग नहा रहे थे और पानी उछार रहे थे। गुरु नानक ने उनसे पूछा कि ये क्या कर रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया--इतनी भी अक्ल नहीं है तुमको। हम सूर्य को पानी चढ़ा रहे हैं। गुरु नानक ने पूछा कि इतनी दूर तक यह पानी चला जाता है तो उन्होंने कहा क्यों नहीं जाता है? इस पर गुरु नानक देव ने भी पानी उछालना शुरू कर दिया। पंडितो ने कहा यह क्या कर रहे हो। गुरु नानक ने कहा कि मैंने खेत में धान बोए हैं, उनको पानी दे रहा हूं। पंडित बोले कि यह पानी तुम्हारे खेत तक कैसे चला जाएगा। तो गुरु नानक ने कहा कि जब तुम्हारा उछाला हुआ पानी सूर्य तक पहुंच सकता है तो मेरा खेत तो इस धरती पर है, वहां तक पानी क्यों नहीं जाएगा; तो यह दृष्टिकोण था कबीर और नानक देव का। लेकिन आप क्या पढ़ाते हैं इनके बारे में? नहीं आप तो पढ़ाते हैं-

"चतुर्वर्ण मया सृष्टम्

गुण कर्म विभाजन:।"

इसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत होगी। शिक्षा में आपको दृष्टिकोण बदलना होगा। तो शिक्षा से पहले आदर्श को समाप्त करना होगा। यदि आप सच्चे

को साइंटिफिक दृष्टिकोण देने के लिये पढ़ायेंगे, साथ ही साथ इक्वैलिटी की भावना उनमें देंगे, सब मानव बराबर हैं, रूसो से लेकर गांधी तक, ईसा से लेकर मार्क्स तक, दुनिया में हर मानव बराबर है, बराबरी की यह शिक्षा देंगे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये उसको साफ करेंगे तो विकास सम्भव है। और बात छोड़ दीजिए 14 या 18 साल तक कम्पलसरी सरकार कर दे शिक्षा के क्षेत्र में तो ठीक है प्रस्तावक महोदय ने बहुत जोर से कहा है कि अपनी भाषा, अपनी भाषा। प्रस्तावक महोदय ने क्षेत्रीयता की बात की। लेकिन इन क्षेत्रों को एक धागे में बांधने का काम कैसे हो सकता है जब तक कि हमारी एक राजभाषा नहीं होगी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और ओखा से मणिपुर तक का हिन्दुस्तान एक दूसरे को तभी समझेगा जब तक एक भाषा बोली जायेगी। अपने इलाके में अपनी भाषा में बोलेगा दूसरी जगह के लिये जरूरी है कि एक ही भाषा सारे देश के लिये हो। गांधी जी ने कहा, सुभाष चन्द्र बोस ने कहा कि इसके लिये फिट है हिन्दी। लेकिन यहां जो थी लैंग्वेज फार्मूला सरकार की नीति है क्या वह कार्यान्वित हो रही है? प्रस्तावक महोदय को अपने मंत्रियों से कह कर कम से कम इस काम को कराना चाहिये। क्या यह जो आपकी नीति है लैंग्वेज फार्मूले को क्या राज्यों में इसका पालन हो रहा है? क्या उन पर यह कार्यान्वित हो रहा है? यदि नहीं तो कौन दोषी है? एक देश को एक धागे में पिरोने के लिये शिक्षा का जो मामूली एलीमेंट है, अच्छी चीज है उसको न करने के लिये कौन दोषी है? यह सरकार दोषी है।

श्री लैंग्वेज फार्मूले की बात तो दूर, देहातों में जो स्कूल हैं उनकी क्या हालत है, क्या आपको पता है? उनको ठीक करके रखो। अभी वर्षा का सत्र है। सभी प्राइमरी स्कूल बन्द होंगे। मकान नहीं होंगे। सब बह गये होंगे, कुर्सी बह गई होंगी, मेजे बह गई होंगी। अगर वहां तक जाने के लिये रास्ता नहीं है तो लड़का स्कूल आना छोड़ देगा, मास्टर स्कूल आना छोड़ देगा। पहले आप इनको ठीक करिये। जो प्राइमरी स्कूल हैं उनको भी सरकार ठीक नहीं करती तब पढ़ कर होगा क्या। पढ़कर भी काम मिलता नहीं। एम्पलायमेंट की बात आती है। इसके लिये सरकार कुछ कर रही है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Please concludes now.

श्री शिव चन्द्र झा: मैं खत्म कर रहा हूं। इन सब बातों को मद्दे नजर रखते हुए जो भी हमारी नीति है उसको यदि सरकार ठीक करे तो बहुत से मामले हल हो जायेंगे।

इस में पावर्टी की बात आती है। इस पर बोलने के लिये एक और प्रस्ताव चाहिए। पावर्टी कैसे दूर होगी जब टांटा बिरला का राज यहां है। मानोपली घराने के कब्जे में भारत की अर्थ-व्यवस्था है। स्वराज्यपाल बैठा हुआ है नाक पकड़ कर घुमा रहा है। पहले वित्त मंत्री को घुमाया लीक आउट करके अब और किसी को घुमा रहा है। अपना सारा पैसा यहां इन्वेस्ट कर रहा है। सारी अर्थ व्यवस्था कुछ लोगों के हाथ में है बावजूद पब्लिक सेक्टर के। प्रस्तावक महोदय यदि इस पर हमला नहीं करेंगे तो बुनियादी फैसला नहीं होगा। बुनियादी इलाज नहीं होगा। लेकिन आप कहेंगे कि इस पर लम्बा समय लगेगा। मैं मानता हूं लम्बा समय लगेगा। लेकिन

[श्री शिव चन्द्र झा]

कुछ कदम तो उठाना चाहिये । लेकिन जैसा भी प्रस्ताव है मैं इसका समर्थन करता हूं । अगर यह कार्यान्वित नहीं हो सके तो कम से कम कागज पर, बोल में, भाषा में, विचार में तो मान लें । इसको मान लिया जाएं । मैं इसका समर्थन करता हूं । यदि यह सरकार नहीं मानती है तो प्रस्तावक महोदय को कहूंगा कि आप बगावत करें और हम आप का साथ देने को तैयार हैं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Heptullah. You have got 15 minutes.

डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला : श्रीमन्, मुझे इसकी बहुत खुशी है कि हमारे मौर्या जी ने इतना अच्छा प्रस्ताव सदन के सामने रखा है । खासतौर से मुझे इस बात की खुशी है कि यह प्रस्ताव सदन के सामने आया । मेरा ताल्लुक तालीम से रहा है । सिर्फ पढ़ने के सिलसिले में ही नहीं, पढ़ाने के सिलसिले में भी जो-जो समस्याएं और जो-जो मश्किलात मेरे सामने आई और अध्यापक के तौर पर जो-जो समस्याएं मेरे सामने आई उनको मैं अच्छी तरह से समझती हूं और इसलिए सदन के सामने अपने कुछ विचार रख सकती हूं ।

जहां मैं मौर्या जी की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि एजूकेशन कम्पलसरी की जाय, 18 वर्ष तक के बच्चों की एजूकेशन कम्पलसरी की जाय, 14 वर्ष तक के बच्चों की एजूकेशन कम्पलसरी की जाय, प्राइमरी एजूकेशन और सेकेन्डरी एजूकेशन को कम्पलसरी किया जाय, वहा मैं यह बात नहीं मानती हूं कि सिर्फ इललिट्रेसी की बजह से ही कास्टिजम और कम्युनेलिजम बढ़ता है क्योंकि कम्युनेलिजम और कास्टिजम पढ़े लिखे लोगों में भी काफी दिखाई देते हैं । मुझे तो ऐसा लगता है कि गांव में रहने वाले जो गरीब और अनपढ़ लोग होते हैं वे एक दूसरे के साथ ज्यादा भाईचारा के साथ रहते हैं बनिस्बत पढ़े-लिखे लोगों के । पढ़े लिखे लोग इन चीजों को ज्यादा करते हैं इसलिए जरुरत इस बात की है कि सही तालीम दी जाय । सिर्फ किताबी तालीम देने से काम नहीं चलेगा । हमें बच्चों को हिस्ट्रिकल तालीम देनी चाहिए ताकि वे कास्ट, क्रीड और रिलीजन से ऊपर उठ सकें । मैं एक उदाहरण देना चाहती हूं ? इस हिन्दुस्तान में मुखतलिफ इलाकों में जहां पर सरकारी स्कूल या कालेज नहीं हैं, जहां पर प्राइवेट इंस्टिट्यूशन्स हैं, जो कास्ट और रिलीजन के आधार पर चलते हैं वहां पर बच्चों के साथ रिलीजन के बेसिस पर किस तरह से डिस-क्रिमिनेशन होता है उस पर विचार करने की जरुरत है । कोई बच्चा जो अच्छी परसेन्टेज से पास हुआ होता है उसको उसमें दाखिला नहीं मिलता है और दूसरा बच्चा जो गिरी हुई परसेन्टेज से पास हुआ होता है उसको दाखिला मिल जाता है । इसलिए आज जरुरत इस बात की है कि समाज में जागृति पैदा की जाय । हमारे समाज में जो खराबियां छा गई हैं उनको दूर करने की जरुरत है । यह सिर्फ स्कूल या कालेजों की तालीम से नहीं होगा ।

हमारे यादव जी बहुत अच्छा बोलते हैं और काफी समझदार भी हैं । उन्होंने कहा कि मैं पढ़ा-लिखा नहीं हूं, स्कूल या कालेजों में नहीं गया हूं, मैं समझती हूं कि यह गलत है । वे बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं । मैं यादव जी से

पूछना चाहती हूं कि आपने इसमें यह संशोधन क्यों रखा ? मैं समझती हूं कि हमें रेट्रोग्रेसिव न होकर प्रोग्रेसिव होना चाहिए । अगर स्कूल और कालेज जो प्राइवेट हाथों में हैं, अच्छे चलते हैं, वहां पर अच्छी शिक्षा दी जाती है तो हमें सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट इंस्टिट्यूशन्स में भी अच्छी एजूकेशन क्यों न हो ? हमारे देश में जितने भी स्कूल या कालेज हैं, चाहे वे म्युनिसिपल स्कूल्स हों या दूसरे सरकारी स्कूल्स हों उनका स्टेन्डर्ड बढ़ाना चाहिए ताकि दुनिया में वे अपना नाम कमा सकें और कामयाबी हासिल कर सकें । यह कहना कि प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया जाय, ठीक नहीं लगता है । बजाय इसके हमें यह संशोधन रखना चाहिए कि सरकारी स्कूलों का स्टेन्डर्ड बढ़ाया जाय ।

मैं इस विषय पर बाद में बोलना चाहती थी, लेकिन चूंकि पढ़े लिखों की बात आई है, इसलिए मैं यह कहना चाहती हूं कि एजूकेशन इज ए मस्ट । मैं यह भी कहना चाहती हूं कि मेरे दादा इस हिन्दुस्तान के पहले एजूकेशन मिनिस्टर थे । उन्होंने हिन्दुस्तान में एजूकेशन पालिसी की बुनियाद डाली थी । हमने यह देखा है कि जो लोग स्कूल या कालेजों से निकलते हैं, जब उनका परसेन्टेज कम होता है तो उनको मेडिकल कालेजों या इंजीनियरिंग कालेजों में दाखिला नहीं मिल पाता है । और वे आखिर में टीचर बन जाते हैं । टीचर को तनख्वाह कम मिलती है । अच्छे पढ़े लिखे काबिल लोग ट्रेनिंग में नहीं आते हैं । उनको सुविधाएं भी कम मिलती हैं, घर भी नहीं मिलता है और उसको इज्जत भी कम मिलती है। जिस आदमी की तनख्वाह सिर्फ दो सौ या तीन सौ रुपये हो वह अपने बच्चों को पालने की ही चिन्ता में रहता है । जिस हिन्दुस्तान में गुरु शिष्य की इतनी बड़ी परम्परा थी कि गुरु द्रोणाचार्य के कहने पर एकलव्य ने अपना अंगूठा काट दिया था वहां पर आज शिक्षा में कितनी खराबी आ गई है, इस पर हमें सोचना चाहिए । आज हमारे मुल्क में एजूकेशनल इंस्टिट्यूशन्स की और अध्यापकों की क्या इज्जत है, इस पर हमें सोचना चाहिए।

उनको कितनी तनख्वाह मिलती है ? जो नेशनेलाइज्ड बैंक के अन्दर

4 PM चपरासी होता है, लाइफ इंशरेंस कम्पनी का जो चपरासी होता है उसको एक स्कूल टीचर से अधिक तनख्वाह मिलती है । वही स्कूल टीचर जिससे पढ़कर कोई विद्यार्थी आगे चलकर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का चेयरमैन बनता है। इस चीज पर आपको गौर करना चाहिए। आपने जहां एजूकेशन की बात की है वहां आप इस चीज के लिये भी गौर कीजिये । एजूकेशन को कम्पलसरी करने के साथ-साथ सबसे जरुरी चीज यह है कि टीचरों को सुविधायें मिलें, उनकी तनख्वाहें बढ़ें, उनके रहने के लिये मकान बनाये जायें और उनको सोसाइटी में वह इज्जत मिलनी चाहिए जिसके वे अधिकारी है । मुझे लगता है कि जिंदगी भर मैं यहां न पहुंचती अगर मेरे पढ़ाने वाले टीचर्स ने प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी और पी० एच० डी० तक ठीक से गाइड न किया होता तो आज मुझे यह तालीम हासिल नहीं होती, इस मुकाम पर नहीं आ सकती थी । इसलिये जब इस साल के बजट में थोड़ी बढ़ोत्तरी हुई एजूकेशन के ऊपर, साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि हमारी सरकार के वित्त मंत्री को यह ख्याल हुआ कि साइंटिफिक एजूकेशन, हायर एजूकेशन पर इतना पैसा खर्चा करने की जरूरत है।

[डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला]

एक बात मैं मंत्री महोदय के सामने रखना चाहूंगी और वह यह कि एजूकेशन के बारे में हमारी एक विशनल पालिसी होनी चाहिए, इसमें यूनिफार्मेटी होनी चाहिए। सारी टैक्स्ट बुक्स जो हैं वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड होनी चाहिए। जैसे हिस्ट्री है उसमें क्या होता है कि किसी प्रान्त में कुछ पढ़ाया जाता है और किसी प्रान्त में कुछ पढ़ाया जाता है। इसका नतीजा यह निकलता है कि रीजनलिज्म बढ़ जाता है और एक दूसरे के खिलाफ भावनायें भड़क जाती है। क्यों नहीं सरकार इस बात पर गौर करती कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट टैक्स्ट बुक तैयार करे और हिन्दुस्तान को प्राइमरी, मिडिल और अपर स्कूलों के अन्दर बच्चे उनको ही पढ़ें। यह जरूरी है। इससे यह फायदा होगा कि सारे देश में पढ़ाई के मामले में यूनिफॉर्मिटी होगी। जहां तक रीजनल लैंग्वेजेज का ताल्लुक है, रीजनल लैंग्वेज जरूर होनी चाहिए। अलग-अलग राज्यों को अपनी लैंग्वेज होनी चाहिए लेकिन जो कामन सबजेक्ट हैं, ह्यूमिनिटीज के सबजेक्ट्स हैं, साइंस सबजेक्ट हैं, हिस्ट्री, जागरफी और सिविक्स है इनकी कामन एजूकेशन बुक होनी चाहिए। इससे एक फायदा यह होना कि जो हमारे यहां ट्रांसफरेबल पोस्ट पर काम करते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, सेन्ट्रल गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स जिन के बच्चों की एजूकेशन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि सेन्ट्रल स्कूल इतनी संख्या में नहीं हैं ताकि सारे बच्चों को उनके अन्दर स्थान मिल जाय, उनके बच्चों को वही पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी, एक बात मैं यह आपके सामने रखना चाहती हूं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट जो किताबें छापता है। बड़े दुख की बात है, आप भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं . . . .

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य : स्वतंत्रता सेनानी नहीं, एक हफ्ते के लिये रखा था पुलिस ने हिरासत में।

डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला : एक हफ्ते रहे थे। उंगली कटा के भी लोग शहीदों में शामिल हो जाते हैं।

मुझे बड़ा दुख होता है, मैं हिस्ट्री की बात कह रही हूं। चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट ने एक किताब छापी जो 14 नवम्बर को हमने तीन मूर्ति हाउस में देखी। उसमें एक Those who fought for the freedom of the country. लेख था। मैं यह नहीं कहती कि उसमें किन लोगों का नाम होना चाहिए था या किन लोगों का नहीं होना चाहिए। मैंने उस किताब को देखा तो उसमें जहां बड़े बड़े नेताओं का नाम था, जहां गांधी जी का नाम था, नेहरू जी का नाम था, और लोगों का नाम था वहां मुसलमानों में सिर्फ मुहम्मद अली जिन्ना का नाम था, वहां मौलाना आजाद का नाम याद नहीं आया, आसफअली का नाम याद नहीं आया। अगर जिन्ना साहब देश की आजादी के लिये लड़े तो क्या बाद में उन्होंने देश के बंटवारे के लिये लड़ाई नहीं लड़ी? यह तो हमारी हालत है। जब हमारी सरकार की तरफ से इस तरह की किताब छपती हो और उसमें इस तरह का भेद भाव किया जाता हो और कहा जाता हो कि Jinnah fought for the freedom of the country and nobody else among the Muslims, then what do you expect from the children who will come out of the school? (Interruptions) If he fought for the freedom of the country, many nationalist Muslims also fought for freedom.

जहां तक एजूकेशन का ताल्लुक है मौर्य जी, आपने सिर्फ यह कहा कि कम्पलसरी एजुकेशन होनी चाहिए 18 वर्ष की आयु तक . . . (व्यवधान)

4·05 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHHI DINESH GOSWAMI): I don't think we should 2° [in]to this controversy. The hon. Member has raised a valid point. The hon. Minister will look into it, and if such discrepancies are there, h$_e$ will see that those are removed.

SHRI BUDDHA PRIYA MAURYA: It is a very valid point.

डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला : मौर्य जी ने यहां तालीम की बात की है। मौर्य जी ने कहा कि 18 साल की उम्र तक तालीम होनी चाहिए। मैं मानती हूं कि हमारा देश जो है यहां पर बड़े-बड़े विद्वान हैं मगर समय के साथ-साथ वक्त बदलता जाता है। उस जमाने में शिक्षा ली जाती थी विज्ञान की, दूसरी चीजों की वह इसलिए ली जाती थी कि शिक्षा प्राप्त करनी है और सिर्फ शिक्षा ही ली जाती थी। मगर आज जमाने के साथ-साथ शिक्षा जो ली जाती है वह कुछ काम करने के लिये, रोजी रोटी कमाने के लिए भी होती है। जहां मैं मौर्य जी के साथ सहमत हूं वहां मैं उसमें यह अडीशन करूंगी कि हमारी प्राइमरी और सेकंडरी एजुकेशन के बाद टेक्नीकल और वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर भी ज्यादा जोर दिया जाए। तभी हमारे देश के बच्चे जो आज स्कूलों से भाग कर सड़कों के ऊपर जाकर छोटे-छोटे, धंधे करते हैं या खेत में काम करते हैं बल्कि वह हाथ फैलाकर भीख मांगते हैं यह हमारे लिये बहुत शर्म की बात है। मैं इस चीज के ऊपर जरा भी बुरा नहीं मानती अगर कोई बच्चा पेट पालने के लिये मजदूरी करता है मगर मेरा सिर शर्म से झुक जाता है जब मैं अपने बच्चों को दूसरों के आगे भीख मांगते हुए देखती हूं। इससे मुझे ऐसा लगता है कि कोई बच्चा भीख नहीं मांगता है बल्कि मेरा देश ही भीख मांगता हुआ नजर आता है। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि ज्यादा से ज्यादा वोकेशनल ट्रेनिंग पर जोर दिया जाए ताकि बच्चे आगे बढ़ कर के कुछ ऐसा काम कर सकें और अपना पेट पाल सकें और उनके हाथ में कोई हुनर आए। मुझे इसके साथ ईरान की बात याद आती है। ईरान के अन्दर जब शाह आफ ईरान ने एजुकेशन कम्पलसरी कर दी तो जो बच्चे थे वे सब स्कूलों और कालेजों में भर्ती कर दिये गये पढ़ने के लिए। उन्होंने यह गौर नही किया कि यह बच्चे शुरू से अपने मां बाप के साथ बैठ कर कालीन बनाना सीखें जो कि उनका परम्परागत और सदियों से पुराना काम है। इसका नतीजा यह हुआ कि चन्द सालों के बाद उनका कालीन का प्रोडक्शन जो था, कारपेट्स का प्रोडक्शन जो था वह खत्म हो गया। इसलिये कि छोटी-छोटी अंगुलियों को ट्रेंड किया जाता है, जब वह नर्म होती हैं तभी से ट्रेंड किया जाता है, तभी वह टांका लगा सकती हैं और बड़ी उम्र तक बिलकुल सीख जाते हैं। तो आपने जहां काश्मीर के बारे में कहा कि वहां एजुकेशन बहुत कम है मुझे बड़ा दुख हुआ। चाहे कहीं की भी बात हो, चाहे कशमीर हो, बंगाल हो, अफ्रीका हो जहां कहीं भी एजुकेशन कम होगी उसके लिए पढ़े-लिखे लोगों को इस चीज पर बड़ा

[डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला]

अफसोस होगा तो मैं यह बात कहूंगी कि अगर काश्मीर या नार्थ ईस्टर्न रीजन में जहां घरों के अन्दर लोग काम करते हैं जहां उनकी इस इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहिए उसी के सिलसिले में मिलाकर उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए जिससे उनको एजुकेशन के इलावा यह ट्रेनिंग भी उनके कोर्स में कम्पलसरी हो ताकि हमारे देश के जो पुराने तरीके, पुराने उद्योग हैं, जो हमारे साथ के काम करने वाले हैं, जो हमारी काटेज इंडस्ट्री है वह खत्म न हो जाएं। यह दो-तीन बातें भी रख लीजिए। जहां तक मौर्य जी ने मुसलमानों को एजुकेशन के बारे में कहा है बड़े अफसोस की बात है कि चन्द मुसलमान इतने पढ़े-लिखे निकले और ज्यादातर मुसलमान कम पढ़े-लिखे निकले। मुझे यह कहना है कि मेरे ख्याल में उसकी दो वजह हैं। एक तो गरीबी इतनी होती है कि आदमी को सबसे पहले रोटी की फिकर होती है बाद में दूसरी चीजें आती हैं। उसको किताब नजर नहीं आती है। जब पेट भरने को रोटी नहीं होगी, तन पर कपड़ा नहीं होगा तो मां बाप उस बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिये नहीं भेज सकते चाहे फ्री एजुकेशन हो, मां बाप यह चाहते हैं की वह दो रुपये कमा कर लाए। उसके ऊपर इंसान को ज्यादा गौर करना पड़ता है। मैं आप को उदाहरण के लिये बता दूं। जहां तक एजुकेशन का ताल्लुक है हमारे प्रोफेट हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहू अलह-ही- वसल्लम का यह कहना है कि उस जमाने में जब कि आने जाने के साधन कुछ नहीं थे तब उन्होंने कहा था कि तालीम हासिल करने के लिये तुम्हें चीन भी जाना पड़े तो तुम जाओ। आप अन्दाज कर सकते हैं कि अरब कंट्री से चीन तक उस जमाने में जाना कितना मुश्किल था। मुझे बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है वही मुसलमान कौम क्यों नहीं पढ़ाई के ऊपर ज्यादा ध्यान देती है।

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य : नाजमा जी, आबादी बढ़ रही है लेकिन लिटरेसी घट रही है।

डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला : जो आप कह रहे हैं वह दूसरी बात है लेकिन मैं यह कह रही हूं कि गरीबी बढ़ रही है, आबादी नहीं बढ़ रही है। आबादी बढ़ रही है किसी भी वजह से हो, गरीबी बढ़ रही है। आपने कामन लैंग्वेज की बात की। मैं अपनी बहन से अभी बात कर रही थी। ठीक है एक कामन लैंग्वेज होनी चाहिए। पर कौन सी लैंग्वेज कामन लैंग्वेज होनी चाहिए। कौन सी लैंग्वेज कामन हो, पहले यह तो फैसला हम लोग कर लें। जहां तक कामन लैंग्वेज का सवाल है मुझे लगता है कि इस सवाल को न उठायें और सिर्फ एजुकेशन के ऊपर ही गौर करें चाहे किसी भी जबान में तालीम दें उनको तालीम देनी चाहिए ताकि उनके लिए तरक्की का फायदा हो। इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं मौर्य जी, आपके इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं और उम्मीद करती हूं कि सरकार इसको मानेगी और ज्यादा पैसा एजुकेशन के ऊपर खर्च करके इसको पूरा करेगी।

DR. MALCOLM S. ADISESHIAH: Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support Mr. Maurya's important Resolution. I support the intention of that Resolution, which is the eradication of illiteracy in India in the shortest possible time.

Now, I would like to begin with first by defining illiteracy, child illiteracy, which Mr. Maurya refers to in his Resolution and that there should be free and compulsory education for

all children up to eighteen years of age. The acquisition of three r's, reading, writing and arithmatic, which is obtained by a child when he completes five years of primary schooling. On that are built the other skills of learning, geography, history, national problems, arid so on. The second type which Mr. Maurya hints at but does not deal with is; adult illiteracy. The definition there also is the acquisition of reading, writing and arithmatic. In addition, the three r's, should be learnt in the context of some income earning skill, which is what the adult is interested in, this is also what the should have. He is not interested in three r's only, but with practical application. And", thirdly, today, particularly for us in India, adult literacy should include not only the ability to read the word but to read the world. This is the awareness, the consciousness of the exploited condition of the illiterates in the country. With this definition of illiteracy, referring to child illiteracy and adult illiteracy, I turn next to the question of numbers. As far as child illiteracy is concerned, my computation is, I see the Deputy Minister of Education here, that there are 70 million children, who are either out of school or who have dropped out before class 5. I see the UNESCO definition of literacy, which is also our definition, is that a child must be for five years in school to acquire literacy. And we will see later on and I will mention to you that our calculation is that "64 per cent of children drop out before class 5, which means that 64 per cent of primary school chilrden are illiterates because they drop out. The figure given by the Ministry is that girls drop out number is 69 per cent, whereas the overall drop out percentage is 64. Now, therefore, child illiterates include, I would say that those who are left out of school. The Government's calculation is that today, as of today, in the case of boys it is 5 per cent, *i.e.* those who are left out, and the percentage of girls in the case of left outs is 38 per cent. That means that according to the latest information that I have that 21 per cent of those who ought to be in school are not in school. If you add this figure of drop outs, which is 64 per cent, and left ours which is 21 per cent, you come to this figure of 70 million child illiterates. Seventy million of the children of our country today have no education and no opportunity. When it comes to adult illiteracy, the number is 240 million.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI); Dr. Adiseshiah. I should not interrupt you, but what would be the percentage in the case of girls? According to you 64 per cent of the girls drop out, what is the left out?

DR. MALCOLM S. ADISESHIAH: The left out, Mr. Vice-Chairman, is 6 per cent in the case of boys and 38 per cent in the case of girls.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI); Sixty four per cent and thirty-eight per cent will make it more than 100 per cent....

DR. MALCOLM S. ADISESHIAH: Left out is one category and drop out is another category. You cannot add up these two things.

SHRI BUDDHA PRIYA MAURYA: The same figures were given by the Education Minister in {he other House.

DR. MALCOLM S. ADISESHIAH: Mr. Vice-Chairman, in relation to Mr. Maurya's Resolution we are talking of 310 million Indian illiterates, child and adult. This is what we are talking of against the figure of 700 million of total population that Mr.. Maurya referred to.

[Dr. Malcolm S. Adises]iahh

The third point I want to make is that he mentioned that whereas illiteracy has been numerically going down in these 30 years, in the sense that enrolment has been increasing, in reality it is not so. In the first fiive years, we have got more than 80 per cent under enrolment and the Ministry believes, and I agree also, that the normal enrolment will reach 100 per cent by 1990; this is possible. But the problem is that 64 per cent of that normal enrolment however join the ranks of illiterates and thus illiteracy in terms of numerical enrolment is increasing. Adult literacy also has been improving, adult illiteracy not increasing in percentage terms but increasing in absolute terms. For instance, in 1951, 81 per cent of Indian adults were illiterate; today it is 64 per cent. Therefore, illiteracy percentage has fallen from 81 *to* 64 per cent. But abso$_r$ lute numbers have increased. It was 17 crores, or 173 million in 1951; today it is 240 million.

The main point where I disagree with Mr. Maurya's Resolution is. I do not believe, as he says that illiteracy has resulted in weakening the fabric of national unity by encouraging fissiparous tendencies in the name of caste and religion. I believe that of course illiteracy has weakened the fabric of national unity; with that part I agree; but those who are casteists or those who are communalists, like me, like him, are all educated people. It is the goondas who bring disunity; all the goondas whether in the North or the South are educated people.

SHRI BUDDHA PRIYA MAURYA: That is why I said they ar$_e$ capable enough to exploit and misguide th$_e$ illiterate people. If the people are literate, they will not be misguided.

DR. MALCOLM S. ADISESHIAH: Mr. Maurya, you know that all the trouble in the world is caused by educated people. Hitler and Nazis were highly educated; Italian fascists were highly educated. Therefore, we must not assume that education will promote understanding. It is not so simple.

SHRI BUDDHA PRIYA MAURYA: I talked of generality; exceptions are there.

DR. MALCOLM S. ADISESHIAH:I support you for two reasons. First of all, I support you if you mean that illiteracy weakens the fabric of national unity in th$_e$ sense that it introduces grave inequalities in our society. At the time of Kot-hari Commission Report, We had an official survey and it showed that 80 per cent of those who finish High School and university education in this country come from the top 20 per cent of the society. In the bottom 80 per cent ar© those who do not finish High School or college education. Therefore, w$_e$ have two groups in our Indian society: the rich and well-to-do people and poor illiterate people. I agree with Mr. Maurya if he means that illiteracy breaks the unity of our society and it creates a pluralistic society with majority of people poor and a rich minority. Therefore, we need to abolish illiteracy in order to move towards an equalitarian society or a socialistic society as provided in our Constitution.

The second reason which is v$"y important for the poor man is, I think, that through education, the poor can improve their earnings. And one way of abolishing poverty in the country is by bringing education to them. But that is not mentioned in the Resolution. Now I just want to say that the Russian Economist, Strumelin in 1921 wrote a letter to Lenin, of which I have a copy, in which he said that all the money that you are now investing in creating these great hydro-electric plants must be supported by parallel investment on education.

He pointed out that one year of primary schooling for workers will increase productivity by 30 per cent, whereas, by working on these dams for one year, productivity improves only by 12 per cent. There are similar stdudies which have been made all over the world which have shown that primary education, improves productivity.

I was examining the World Bank report. It is seen therefrom that those countries which have 70 to 90 per cent illiteracy have a per capita income of Rs. 1.00 countries which have 50 to 70 per cent illiteracy have double that per capita income-^we are in this category—Rs. 2,400, and those countries which have ten per cent illiteracy only have a per capita income of Rs. 8,000. This is a clear evidence to show that literacy means improved productivity, improved skills and improved earnings. And studies which have been made by us, economists, in India show that the highest rate of return comes from primary education and literacy. The figures vary from 16.1 per cent to 20 per cent. The return on educating a child and adult is the highest, at the first level, primary level, whereas the lowest rate of return *(6*—8 per cent) comes from B.A. and B.Sc. I would, therefore, say to the Government— and I have said this to my Government— 'Please spend less money on college and university education and spend more moeny on primary education and on literacy' because this is what is paying the country. Now, the question is, where do we go from here? I believe, what is needed in the case of child literacy is not more money. It is better use of the enormous amount of money which the Government i has allocated. I must congratulate the Government. From the start of the First Plan, we have been putting enormous amount of money into primary education. But we have not been using it adequately so that we have this problem of drop-outs. Recently, a sociologist made a study of drop-outs. He found that if the children in a particular village, who were spending their time in the sugar plantations, cutting and earning money, went to school, instead of working in the sugar plantations, the family will starve. Therefore, the problem of drop-outs is linked to the problem of poverty and the only way we can solve the problem of drop-outs and left-outs is by making sure that the parents get some money in order that their children can go to school.

As far as adult education is concerned, adult literacy is concerned, I would like to say that in the Frst Plan, we spent only Rs. 5 crores out of Rs. 153 crores which was the amount allocated for education; in the Second Plan, Rs. 4 crores out of Rs. 273 crores; in the third Plan, Rs. 3.3 crores out of Rs. 597 crores; in the Fourth Plan, Rs. 4.5 crores out of Rs. 786 crores and in the Fifth Plan, Rs. 8 crores out of Rs. 1,286 crores. This shows that the proportion of amount spent on adult literacy out of the total amount allocated for education has been coming down. It was 3.3 per cent in the First Plan, it came down to 1.5 per cent in the Second Plan, to 0.5 per cent in the Third Plan, to 0.6 per cent in the Fourth Plan and to 1.4 per cent in the Fifth Plan.

Mr. Vice-Chairman, I was a witness to this. One of the contributions which Mr. Morarji Desai made, and he got the Janata Government, his Government, to go along with him, was to put adult education as a priority item for the first time in India and he allocated Rs. 200 crores for it in the draft Plan 1978—83. Now, the present Government has taken up the programme and has allocated Rs. 128 crores out of Rs. 2,500 crores. This means, a jump from one per cent to five per cent has been made by the Government. This is really a breakthrough. I must say to you, Mr. Vice-Chairman, it is not the Government which is now lagging. It is we, the intel-literacy, I remember, when Mr. Morarji Desai allocated Rs. 200 crores for adult literacy, I was the Vice-Chancellor of the Madras University at that time. My colleagues, other Vice-Chancellors come to me and told me 'Let us go and meet and tell Mr. Desai 'why are you wasting this Rs. 200 crores, money on ault literacy?: give this money to us. The University Vice-Chancellors did a big propaganda at that time. Today Mr. Vice-Chairman; I must honestly say that the intellectuals do not believe that primary education and adult literacy is the fir-.t priority. They believe that university education, higher education and research are important.

[Dr. Malcolm S. Adiseshiah]

Therefore, may I say that the political will shown by the Government, where Shri Maurya referred to the statements of Mrs. Gandhi and the increase from Rs. 5 crores in the Fifth Plan to Rs. 128 crores in the Sixth Plan, big jump, that must be supported by us?

Finally, Mr. Vice-Chairman, I think the implementation does not depend upon Mrs. Sheila Kaul or Mrs. Gandhi, it depends upon the State Governments, the districts, the blocks and the Panchayats. It is there that we are weak and they should be strengthered.

Now Mr. Maurya mentioned the city percentage of literacy. T have got the figures here. I think the worst illiteracy is to be found in U.P. there it is 88 million, in Bihar it is 51 million, in Madhya Pradesh it is 37 million, in Andhra Pradesh it is 37 million, in Maharashtra it is 33 million and in West Bengal it is 32 million. In all these states it is about 30 million. So, these are the six Slates which are in the most serious position. If any priority is to be give[1]! by the Government, State and the Centre, I would say that these six states should be given the priority. Kerala, Punjab and Tarnl Nadu are in a favourable position as far as literacy is concerned. I am afraid, Mr. Vice-Chairman, now this 'literacy' would be another new factor dividing our country into States which are more advanced and which are backward. We have got other things making us forward and backward States, but literacy might be one of them. Therefore; I believe, all efforts should be made at (he State level, district level, to implement this excellent programme. And there I do not agree with my friend Shri Hukmdeo Narayan Yadav who put forward a resolution to abolish public schools. Well, he says 'private schools', but he means public schools, be means the convent schools, he means the Delhi public schools. First of all, this is a reflection on the society's inequality. If our society is unequal, education will also be unequal. You will not make society equal by just abolishing the schools. In fact, these schools are means by which voluntary agencies are contributing to the innovative nature of the education system. There fore, I believe that in this area of child literacy and adult literacy where all—all, Centre, State, village Panchayat raj institutions and voluntary agencies should work together, and to that extent I do not agree with Mr. Hukmdeo Narayan Yadav's resolution and support the resolution of Mr. Maury a.

SHRI NEPALDEV BHATTACHARJEE (West Bengal): Thank you, Mr. Vice-Chairman, for giving me this opportunity to speak on this Resolution. Hon. friend Maurya has asked for *khule dil se samarthan.* I will support this resolution but not wholeheartedly. I can but open my heart to support him with a little doubt, while explaining the Resolution, he correctly mentioned something but h$_e$ is absolutely correct on some wrong points. You' have never explained why after 35 to 36 years you had to move this Resolution, what the reasons are behind this Resolutio what the social and economic background is which prevented you from eradicating illiteracy from the country. You never spelt out this aspect. I do not know whether you want to bypass this aspect. What your desire is I do not know because you are on that side and it would be very difficult for you to say that it is the Central Government which is responsible for this huge illiteracy which has com$_e$ from 302 million to about 400 million according to 1981 census.

[The Vice-Chairman (Dr, (Shrimati) Najma HepdiHa) in the Chair] Who is responsible for that? How are you ?oing to change it? Only one change in our Constitution will not change the situation. Whatever figures you may give, or on. my part I can give, the question is, what is the fact? The fact is this that the percentage of literates is remaining static because it is just what is required to run this economy, to run this society. As it was said by the British, the motto of education in our country is still the same. That is why despite whatever was written, in

our Constitution in Article 45—you have read it out; I do not want to read it out— I about children upto the age of 10 or 14 getting free education, they will not get it. The reason is not spelt out. Hut let me say this. You may differ wih me. The reason is that if you produce more literates, it will cause harm to the classes which are ruling the country. That is the basic reason behind it. I know. it is very difficult for you to say so because you are on that side. But if you go and examine the situation why after 36 years of Independence, you are bringing this Resolution, if you are alone and there is nobody to reply to, and if you ask yourself, the only reason you will find is this. The rate of illiteracy in our country has remained static at 70 per cent almost because only 30 per cent is required to produce what we are producing now. This is the number of engineers required. A certain number of engineers are required to produce all this, the Tatas, Birlas, Dalmias and Singhanias— whoever are there— require only 30 per cent of the engineers. The MBBS medicos or the students who are passing examinations are fa> those who can afford to pay Rs. 10, Rs. 20, Rs. 50 or Rs. 60 as fees for just getting a prescription. But 70 per cent illiterates have remained where they were.

Dr. Adiseshiah also said that the Central Government is spending enough. But I cannot understand one thing. While other States in Asia are spending so much on education, why are we ao: spending as much? According to the UNESCO Report— I will read just one sentence because I do not know wha' is the tirna allotted to me, only the Vice-Chairman can say ...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. (SHRIMATI) NA.TMA HEPTULLA): Everybody is to speak for 15 minutes. If you speak less, I will be very happy.

SHRI NEPALDEV BHAITACHAR-JEE: I will definitely like to make you happy.

I just ant to read one sentence from the UNESCO Report for Mr. Maurya:

"Unfor ..'entely, the. corresponding figures will show a rapid r*: iro>n 55 per cent to 70 per cent ..."

i.e. mass illteracy percentage—

"..in Asia mainly due to large increase in the number of illiterates in India."

अगर एशियाड में इल्लीट्रेसी का कोई आइटम होता तो गोल्ड मैडल हमको मिलता।

You never said why it is so. When a State like Brazil is spending 3.4 per cent out of their whole budget ...

DR. MALCOLM S. ADISESHIAH: Of their national income.

SHRI NEPALDEV BHATTACHAR. JEE: when th$_e$ percentage of illiteracy is 33.3, we are spending only 2.8 per cent when our illiteracy percentage is 70. What exactly is the reason for this? So I have to differ with Dr. Adiseshiah when he says that enoimgh money is being spent on education.

DR. MALCOLM S. ADISESHIAH: On primary education.

SHRI NEPALDEV BHATTACHAR-JEE; I agree with him that money is not being spent properly. I also want *to* differ with Dr. Najma Heptulla, who is now sitting in the Chair, but who was speaking at that tim$_e$ from that side, that more attention should be paid to higher education. I want to know from you, while you are placing this Resolution here, what the basic conception of education is. What is the basic concept of education? Do you want everybody *to* have Ph.D., or mass education? There you lack one thing— I am sorry to say that—and that is political will. If that will is there, everything is possible. I can give you *one* example, that of Vietnam. In 1954, in one part of Vietnam, North Vietnam, the President, who was the beloved leader of the working class of the world, Ho Chi Minn, gave a call to reverse the number. The percentage of literates was 27. He said, "Reverse.

[Shri Nepaldev Bhattacharjee]

Make it 72 in two years." They made it [7] 7. It is a question of political will. That you have to ask yourselves. While [1] placing this Resolution, vou hav$_e$ to ask whether those who are in the ruling party for the last 35 years and who are in the Government are having this political will' or rot. This is the question.

Take the case of West Bengal Very correctly Dr. Adiseshiah pointed out, "What can the Panchayats do? Why will a child go to primary school if he is earning Rs. 2. by way of collecting woods from a forest?" That is why the West Bengal Government is spending Rs. 30 per family if the parents send their child to the school.

AN HON. MEMBER; What is the average turn-out?

SHRI NEPALDEV BHATTACHARJEE: I am telling this. For the tribals, for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes it varies. Th$_e$ minimum is Rs. 30 that they are spending by giving it to the parents to leave their child in the school. That is No. 1. No. 2, they are provided food, clothes and books free.

The question is that in this Resolution it is not there as to what mode of education should be there, whether it should be higher education on which we should give more emphasis or more emphasis be given to higher education. Shrimati Najma Heptullah was asking for more emphasis on mass education. That is where the question of literacy and illiteracy comes. Our whole attention up till now been on higher education. It was an honest confession by the ex-Vice Chancellor of the Madras University that th$_e$ vice-chancellors and the intellectuals ar$_e$ asking for more and more emphasis on higher education and also that we are a part of that. I am also in a students' organization. We also do the same mistake saying that more facilities should be given for it, and not for the other level. Why?

I have to repeat. I do not know whether you deliberately tried or not, but you tried to derail th$_e$ discussion bringing religion into education. It is not only the Muslims who arc responsible for it. The Hindus arc also responsible for it. You can give some figures and say that where the Muslims are in good numbers the percentage of illiteracy is higher. That may be true. But you canot justify the whole thing, whatever has been happening in this field since Independence. You cannot justify by saying that religion is responsible for this or for that. All of us are res-posible. And the topper of the list is the Central Government, those who have been ruling since Independence. It is rot we because I am from a different party., It is not we who are a party to this wrong attitude towards education. In West Bengal, whatever we can do in regard to education, we are trying to do. So many things you have heard. 1 am saying another thing. We are spending 24 per cent of our total budget on education. It is so because we agree with what Dr. Adiseshiah said right now, that it gives a better output. It will give us dividends, tomorrow or day after tomorrow, if we spend more on education. That is what we are trying to do. Our whole attitude is towards mass education. That is why we are spending more than 40 paise per head, whereas the Central Government is not spending evert 4 paise per head. There again I have to come to the old phrase that I have already said that it is a question of 'political will'. *(Time bell rings).*

I am within twelve minutes or something like that.

THE VICE-CHAIRMAN DR. (SHRIMATI NAJMA HEPTULLAH): I am giving you the indication. Another two ' minutes, you can take.

SHRI NEPALDEV BHATTACHARJEE: I just want to mention one thing. Again I have to differ with you, Dr. Adiseshiah. It was 4.30 per cent in the First Plan out of th$_e$ total Budget. In the Sixth Five Year Plan it came down to 1.1 per cent. How is it? My difference with you is only this. What exactly do we want to do by reducing the amount of expenditure from 4.39 per cent to 1.1 per cent? Exactly what do we want? Again I have *to* say that this is a question of attitude. One resolution will not do. Tonnes

of resolutions you can print. Thousands of resolutions we .can pass. Gallons of tears we can shed from our eyes. They can be crocodile tears. That can make the roads slippery. But what exactly do you want *to* do? I whole heartedly support the Resolution.

मैं इसका होलहार्टेड सपोर्ट करता हूं, समर्थन करता हूं। लेकिन यह पूछना चाहता हूं कि पिछले 35 सालों में आपने इसको क्यों नहीं किया? सिर्फ इसलिए कि आप उस तरफ बैठे हुए हैं, इसलिए इस तरह का प्रस्ताव लाये हैं। थोड़ा आप इस तरफ भी दिमाग लगाइये, ध्यान दीजिये कि पिछले 36 सालों से आपने इसको क्यों नहीं किया?

Why? While supporting your Resolution 1 tell you that it is not going to be implemented. There is no Government in India which can implement it. Even if all of us agree cent per cent, 110 per cent, with this Resolution, there is no Government to implement it. Since the Independence there was a break of only two-and-a-half years when you can say that another Goverrment came. Otherwise it is father and daughter only, except five years. There is no political will, and there is no political conception. There is no attitude towards education which can implement *your* Resolution. You have gone from 14 to 18. Thank you very much for adding four years more. Let us finish 14 years.

SHRI BUDDHA PRIYA MAURYA: Education has been a State Subject and then it was also made a Concurrent Subject. What are the States doing.

SHRI NEPALDEV BHATTACHAR-JEE: What are the States doing? I have given the example of one State from where I am coming. It is 24 per cent. And you can speak about the States from where you arc coming. It will be nice then. Let us speak about our States. Most of the States are ruled by the same party which is ruling the Centre.

Again i am coming to politics. I am coming from a political party. I cannot throw away my political ideas.

I am giving my wholehearted support to your Resolution. But it is not going to be implemented. There is no Government at the Centre which can implement it. With these few words I support your Resolution, opposing obviously that part which, is saying that illiteracy is responsible for those maladies. I oppose it because I do not believe.

I also share the view of Dr. Adiseshiah, that it is we, literate persons, educated persons, who are dividing the country: it is not the illiterate. We are planning for that *(Time bell rings)*

Is it over? Thank you, Madam.

SHRIMATI USHA MALHOTRA: (Himachal Pradesh): Madam Vice-Chairman, I must thank you for the opportunity that has been given to speak on this burning topic.

I must congratulate my honourable colleague, Mr. B. P. Maurya who has brought this very relevant Resolution which ought to have come much earlier. But I must say that he has risen to the requirement, the need of the hour, today. Before I go on to support this Resolution, I would like to say that just now my hon. colleague from the opposite side said that we had a whole 35 years to plan and implement the educational system in this country. Let me tell him that because from time to time we had been reviewing our education system, today India stands out as one of the biggest sources of man-power for skilled people. Today you see the monumental achievements that we have made in the fields of technology, science and industry. I must congratulate the Government on this achievement. But at the same time, I would say that the legacy which had been left over by the British to us by way of the educational system is probably something that we should have done away with absolutely much earlier. There has to be a radical change; there has to be a pragmatic solution to the whole problem. I share the concern *of* all my hon. colleagues in this House and of the country at large. It is through education that we seek

[Shrimati Usha Malhotra]

to better ourselves, better ourselves as individuals, and to shape our consciousness according to the requirements and needs that our country poses and the global situation poses to us today.

The growing number of illiterates in the country are responsible, according to me, for weakening the society's fabric today. The moral values have been eroded; human values are being thrown down the drain. Why? It is only education that rounds off all the angularities in a person. It shapes you to face the situation; it improves and works on you to become a good citizen of yuor country and a citizen of the world at large. The national character today faces a crisis. Why"! Because there is no respect left for the follow-human being. The social concern has to be there. I think if the social concern is not there, then the society will seem to decay. I feel that through this forum, through this august House, we are able to raise a big question in the hearts of those who seek to improve upon the society and to make it a vehicle of development in this country. If the national character is damaged, r think national unity also faces quite a serious situation. Today the regional parties have raised their heads. Why? What I feel is that the nationalism which should have come through the national character is not there. 'T^IF?

Education would help us to see the problems in the right perspective—problems that face us in a family, which is the basic unit of a nation, problems that face the country and the various regions in our country. Fissisparous tendencies and activities have been* let loose and there is a hue and cry raised on the basis of caste, creed, religion, race, language and what not—everything on the face of this earth. It is quite frustrating at times. I think we should not lose heart. We have a rich cultural heritage that stands stoutly with us. It has saved us from times immemorial. I would say that as compared to the West, we have stood well the impact of those winds of change which have crossed over the boundaries of different countries, These winds of change have not spared us also. Good or bad, they strike al lof us at our roots. We are lucky as compared to the rest of the countries of the world. India has been able to just take *m* a fraction of the turbulence that is all over. I have been all the world over, and I tell you the complete erosion of human values and moral values have led to so many social evils that I do not find words to express over there. The entire fabric of that society — they call it developed — 1 think there is a big backslide in that. We still maintain certain values here. We are proud of it. But at the same time our head hangs in shame when we think of the problems that we create. We seek to remedy them through the Government, through the policies and programmes of our beloved Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi. Family planning was taken up. What happened. The political parties tried to cash upon it, to turn it to their advantage. It was a. national programme in the national interests, and it was given a different colour. Why? Because I think the regional parties or the political parties sought their interests far above the national interests. I would urge upon my friends across the floor, there is very little time left now. Mark my words — you have to cooperate to see that we pull ourselves out of this crisis. It is not merely a question of education. It is a question of moral ralues. Each one of us, as citizens, responsible citizens, has a duty to perform. My honourable friend just mentioned about the fundamental rights. But I know he is very sure and each one of us is sure that to every right there is a duty entailed to it. There should be heart-searching, in every Indian whether that duty is being performed or not. Duty towards oneself does come in, but duty towards the society from which we draw such a lot, should precede. There is so much give-and-take. Have you seen that the society is in good health? I think education does come in at that time and education is the answer to better ourselves, to better our records. We see s« many things around, anti-social activities, anti-social elements, anti-itational elements, going round surreptitiously, trying *to*

strike at the very roots of our nation, only to carve out a place for themselves. That was what (he British left us with us a parting gift. They tried to play one ground against another, one religious group against the other. We realise independence is there. We realised it only so far as our rights are concerned. As far as duties are coijcernd, we say what is the Government doing about it? Let me ask each one of us as to how much we are contributing towards the implementation programmes in the different regions? There has to be involvement of the people around by the masses. In that we come to teachers. I think teachers are the worst sufferers. They do not enjoy the same status, they do not enjoy the same respect from the students. Why? We have to think about it. It is because education is lacking at some point a vital approach which probably could have sorted out this problem. Yes; have we realised that all that we have done to improve, has been diluted by the population explosion? Have we realised that we have added another sub-continent by way of population to what we had when the British handed over India to us? It is very well for the Opposition parties to come up and say, "Well, what have we done after 35 years?".

Let me ask them this question. When we really wanted something to be done on the family planning front why did they come as obstacles and tried to divert the attention of the nation from what was much needed at that time? And today see the magnitude of the problem.

Education should be there. But I would say that we have to give a new dimension to it. My hon. friends over here on the Treasury Benches and across have given statistics. I will not waste more time in giving statistics. But the population explosion and the population growth is like a canker eating into the very vitals of the society. I think this population explosion could b$_e$ attributed to illiteracy. I would say no. There is a socio-economic background to the[1] whole problem. We have diverted so many items of our twenty-point programme for rural development and that is the reason why today you find more literate people. They have more duties on them. The problems are colossal. 1 think there is a Herculean task before us. A colossal effort has to be made to sort all that out. I believe that a national policy on this issue has to be framed. Let it not be too late. Let education be a Central subject. Let our youth get a uniform education and uniform opportunity in all the four corners of the country. There are oackward States; there are advanced States. The educational system is quite different. In other countries which have progressed, I think they have seen to it that there has to be a binding or cementing force and that comes through the mother tongue. We 'have' to assert that we have to have a mother tongue and it has to be in clear terms Hindi. Why? It is not because $_0$f North versus South. It is the need of the hour to bind us all together. We in the North are prepared to learn the languages of the South, with open heart. I tell you we have no inhibitions about that. They are our languages; they are all Indian languages. The education system has to take in itself the language problem first. It is only through language we can impart education. There has to b$_e$ a medium and it has to be language. Let us all put our heads together. We have South Indian languages, we have Urdu, Punjabi, Malayalam, Tamil etc., and have Bengali. They arc our languages. Let us be proficient in those languages also. We do not object to it. There are countries all over the world which are going in for so many languages at the same time. But basically, the regional language should be the language in which the student has to be imparted education. When the students go to the higher classes or have to go out of their respective States, they have to have one cementing language that should be Hindi. Later on, if need be, there has to be an international language. And that international language should be English. I had been to Russia, China, the States and to the European countries. I think I had

[Shrimati Usha Malhotra]

been to all over and I have seen that people who do not know English get lost. Here again it is education which grooms you to be the citizens of the world. For that you have to hav$_e$ Hindi and English, both.

AN HON. MEMBER: Why?

SHRIMATI USHA MALHOTRA : Hindi why? Because it is unders;ood or understandable in the North and now also in the South, East and West — it is only a question of degree. But there has to be a transition period. There 5 p.M. has to be a transition period till the South also picks up and we also pick up from the South and there has to be an attitude of give-and-take and we should feel that we are from the same country. There is no denying the fact that we have a rich cultural heritage.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA): You have to conclude now; you have already taken fifteen minutes.

SHRIMATI USHA MALHOTRA: 1 would like to mention in this august House that we are fortunate in having a leader in our beloved Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi, and we are fortunate to have the superb socio-economic programmes that she has given for all of us to implement and we have to see that they are carried to the lowest rung of the ladder. We have to have the machinery for it and it is no use drawing up policies without the machinery. It is no use drawing up programmes if the implementing machinery is not also with you. So, the help of that machinery is also to be taken. We cannot *throw* it away by saying that it is bureaucracy and it stands in our way. We are there; they are there; and our roles are complementary and supplementary. We can sit across the table and we can sort our our problems and come to a solution. Of course, a direction has to be shown at one stage or the other and the time has come when we cannot and the nation cannot wait any longer. We have to decide upon one common language and we have to decide on adopting a give-and-take attitude in the North and in the South. It is India first and India last. That attitude should develop. We have to preserve the unity and integrity of our country. Regional parties have come up now. Why? The system was different, the approach was different, and I blame this on the British legacy which was handed over to us. I blame that legacy only for this because in it were the seeds of anti-nationalism and the anti-social activities that are being pursued by the society now. They did not want India to be one; they wanted India to be disunited only. So, before they left, they saw to it with care that India was divided. Of course. Madam Vice-Chairman, you mentioned that there was a great contribution from the Muslims as well. Yes. They are our brothers and that was why the remorse was great when they parted. They belong to us and We belong to them. Today, even if someone says that Pakistan is there, it is very difficult to believe that they are a separate entity or that they are having a separate culture or that they are a separate nation because we have common links. There may be something in between. But education did make us feel as one. The cultural heritage that we have inherited does not come in between them and the rest and create any better. But we have to demolish the walls of hatred and we have to build bridges of friendship. This is what education teaches us to do. The fact is that we have to have a national policy in education and We have to have a national language. We have to adopt a policy on our national language. I can give you the details of the reforms that have to be carried out. I talked about the language question. I mentioned about the regional language through which we can impart education. Education is the birth-right of every child and our education should be vocationally oriented and it should not be just degrees being handed over or gold medals being banded over to the students. Vocational education is the need of the hour. If India

has to be selfrelianl and self-sufficient— I think every individual has to be self-reliant and self-sufficient — education should be vocationally oriented and the people should not have to wait for the Government to give them employment or a white-collar job. He should be trained in such a way that he is able to launch himself into the world. Of course, the guiding hand of the Government, the parents, the society is there. But. after all he has to stand on his two legs. You can not give props to anyone, be it individual, be it family, be it city, be it the country or anyone. This starts right from there, and I think the basic need of the hour is vocational education. Even if there are drop-outs, let these drop-outs carve out a place in the society itself meaningfully. Let them not indulge in anti-social activities. The youth is the hope of tomorrow. If children live on the road without being cared for, they will fall into wrong hands and wrong direction. It is this education which will make them better persons. The youth should be employed. I believe in the dignity of labour. They should come out as respectable citizens. *(Time bell rings).*

THE VICE-CHAIRMAN (DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA); We will continue the Resolution on the next to next Friday. Ushaji, you have taken 23 minutes already. If you wish to finish in thiee minutes you can do so. Or we shall take it to next . . . *(Interruptions) lions)*

SHRI BUDDHA PRIYA MAURYA: So many Members have to speak. Let it be carried on the next Friday. *(Interruption).*

THE VICE-CHAIRMAN (DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA): The debate will continue. If she wishes so,. . ..

(Interruptions)

श्री शिव चन्द्र झा : मेरा पोइन्ट आफ आर्डर है, सुन लिया जाय। प्राइवेट मेम्बर्स रिजोल्यूशन के बारे में यह हो चुका है कि ढाई घंटे में उस को खत्म कर लेना चाहिए, एक आदमी का रिजोल्यूशन उसी दिन खत्म हो जाता है, यह फैसला हो गया है, तब मैं जानना चाहता हूं कि किस आधार पर इसको बढ़ाया जा रहा है ? अढ़ाई घंटे की जगह आप पांच घंटे कर दें लेकिन आज खत्म कर दें। दूसरे आदमी का हक क्यों मारा जाय ? दूसरे को मौका मिलेगा। दूसरे का मौका खत्म हो जाता है।

उपसभाध्यक्ष (डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला) : झा साहब, शायद आप होंगे नहीं, जब मौर्य जी ने रिजोल्यूशन मूव किया था तब जो चेयर पर बैठे हुए थे उन्होंने यह बात मान ली थी कि जो प्राइवेट मेम्बर का रिजोल्यूशन है वह आगे भी चलेगा तब आप को एतराज करना चाहिए था। अब तो बात खत्म हो गयी।

(Interruptions)

We will t£(g $_{U}$p this Resolution again on the 12th August, 1983. Smt. Usha Malhotra will continue. Now, I have to make an a-inouncement.

ALLOCATION OF TIME FOR DISPOSAL OF GOVERNMENT AND OTHER BUSINESS.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA); I have to infor$_{m}$ Memhers that the Business Advisory Committee at its meeting held today, Uie 29th July, 1983, allotted time for Government legislative and other Busine$_{ss\ as}$ follows-.